

प्रदेश प्रभारी का नया तेवर, सरल पहरा और भैया वाली राजनीति पर ब्रेक



छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ आते ही सत्ता-संगठन के समीकरण बदल गए हैं। सहज और सरल माने जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अब मजबूत सुरक्षा कवच मिल गया है,

जिसका असर सरकार और प्रशासन पर दिख सकता है। स्मृति ईरानी के आक्रामक तेवर ने उन नेताओं की अकड़ ढीली कर दी है जो वरिष्ठता और घाँस के बल पर सियासत चला रहे थे। अब कुर्सी पर बने रहने और वज्रुद बचाए रखने के लिए परफॉर्मेंस ही एकमात्र पैमाना होगा।

अब सिर्फ काम और परिणाम छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चली आ रही भैया वाली राजनीति यानी मेल-मिलाप और बिना जवाबदेही की सियासत के दिन लंद गए हैं। स्मृति ने रायपुर पहुंचते ही स्वागत

प्रेशर की राजनीति बंद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने मृदुभाषी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी यह सहजता कई बार प्रशासनिक फैसलों में भारी पड़ रही थी। साय मंत्रिमंडल में अधिकांश नए चेहरे होने से कुछ वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों और रसूखदार विधायकों का अप्रत्यक्ष दबाव बना हुआ था। नीतिगत फैसलों में देरी पर उंगली सरकार पर उठती थी। ऐसे में स्मृति ईरानी को भेजना सीएम की सरकार को मजबूत सुरक्षा कवच देने जैसा है। उनके सख्त निर्णयों ने मुख्यमंत्री के लिए उन फैसलों को लेना आसान कर दिया है, जिनमें पहले असहजता महसूस होती थी।

नए संगठन महामंत्री पर नजर

मंत्रिमंडल गठन के बाद से विभागों में वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप और मंत्रियों-संगठन के बीच तालमेल की कमी को लेकर सुगबुगाहट थी। अब नए प्रदेश महामंत्री (संगठन) कर्मवीर सिंह और प्रभारी स्मृति ईरानी की जोड़ी ने दबाव की सियासत पर प्रहार किया है। अब सरकार में किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी नहीं, सामूहिक और अनुशासित निर्णय सर्वोपरि होंगे। बिलासपुर से रायपुर और सरगुजा से बस्तर तक संदेश साफ है सिफारिशों के दिन खत्म।

की औपचारिकता को दरकिनार कर सीधे फील्ड रिपोर्ट पर बात की। केंद्रीय नेतृत्व का संदेश साफ

मंत्रियों-विधायकों पर कड़ा पहरा

स्मृति द्वारा लाई गई जमीनी रिपोर्ट और मंत्रियों के कामकाज के पोस्टमार्टम ने हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली से पूरा होमवर्क करके आई प्रभारी ने सुस्ती दिखाने वाले मंत्रियों की फेहरिस्त खोल दी है। दीपावली से पहले या राज्य स्थापना दिवस के आसपास संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की तलवार सुस्त मंत्रियों पर लटकी है।

जमीनी कार्यकर्ताओं में लौटी ऊर्जा

इस कवायद का सकारात्मक पहलू मैदानी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। सत्ता आने के बाद खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे और वीआईपी कल्चर से त्रस्त कार्यकर्ता राहत की सांस ले रहे हैं। स्मृति के दौर ने साबित किया है कि भाजपा हवा-हवाई दावों के बजाय कैडर-बेस्ड और रिजल्ट-ओरिएंटेड कार्यशैली की ओर लौट रही है। आगामी नगरीय चुनावों के लिए भाजपा अब पूरी तरह फाइट मोड में है।

है कि यदि संगठन और सरकार में रहना है तो नतीजे देने होंगे। जो नेता

मंत्रियों से नाराजगी के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, 'नो कमेंट्स।' वहीं, मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, 'जिसके ऊपर दायित्व होगा, थोड़ी शिकायत तो होगी ही।' बैठक के बाद कई मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए नजर आए। मंत्री लखनलाल देवांगन अन्य मंत्रियों के निकलने से करीब एक घंटे पहले ही कार्यालय से रवाना हो गए।

कागजी बैठकों और बयानों से काम चलाते थे, उन्हें अब बूथ स्तर तक पसीना बहाना पड़ रहा है।

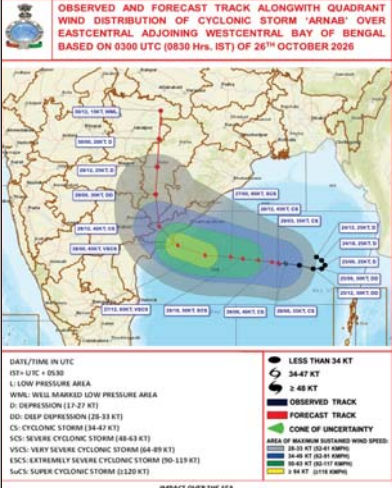
चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ को लेकर छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट

आंध्र तट से टकराकर पहुंचेगा छत्तीसगढ़, भारी बारिश का अलर्ट

कलेक्टरों को 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष एहतियात बरतने के निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ अब खतरनाक रूप ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 26 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे की स्थिति में जो ट्रैक जारी किया है, उसके अनुसार तूफान इस समय पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और लगातार पश्चिम की ओर, आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार अभी तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 35 से 45 नॉट यानी 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। आने वाले 24 घंटों में यह और शक्तिशाली हो जाएगा। इधर चक्रवाती तूफान का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तेद हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर 5 वजे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के

सब्जी बेच रहे पति ने पति से कहा-आराम करने जा रहा हूँ, लटक गया फंदे पर छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के महामाया मंदिर के पास सब्जी बेचने वाले एक युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोतवाली पुलिस मामले में मर्ग कायम कर अग्रिम जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, इंद्रदेव प्रजापति पिता कट्टू प्रजापति 20 वर्ष मूल रूप से झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत गारू थाना क्षेत्र के ग्राम हेंगार का निवासी था, और वर्तमान में अंबिकापुर में महामाया मंदिर के पास अपनी पति और 3 वर्ष की बेटी के साथ रहकर सब्जी बेचने का काम करता था। मृतक की पत्नी सुधा देवी ने बताया 25 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे दोनों पति-पत्नी मंदिर के पास सब्जी बेच रहे थे। इसी बीच इंद्रदेव आराम करने की बात कहते हुए घर चले गए। कुछ देर बाद सब्जी के पास गाय के आने पर उसे भगाने के लिए पत्नी अपने पति को आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने गई तो फंदे पर पति का शरीर लटक रहा था। आसपास मौजूद लोगों की मदद से पति को फंदे से नीचे उतारकर ऑटो रिक्शा से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर गई, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे शाम 7.10 बजे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।



किसानों को फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने तथा चक्रवात से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने व एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने कहा गया है। उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अंतिम विदाई के पहले उजाले का दान, स्व. ओमप्रकाश अग्रवाल की आंखें देखेंगी दुनिया

शोक की घड़ी में स्वजन ने लिया नेत्रदान का फैसला, सूचना मिलने पर देर रात डॉक्टरों टीम पहुंची घर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कहते हैं कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके कर्म और उसकी सोच समाज में जिंदा रहती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अंबिकापुर के प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार ने। अपनों की खोने के गहरे दुःख के बीच परिवार ने जो संवेदनशील फैसला लिया, उसने न सिर्फ एक परिवार की सोच को बदला है, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए नेत्रदान को लेकर एक नई जागरूकता और प्रेरणा पैदा की है। शहर के ओमप्रकाश अग्रवाल का निधन 25 अक्टूबर को रात्रि 9.45 बजे हो गया। घर में मातम पसरा था, परिजन शोक में डूबे थे। इसी बीच उनके पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आम तौर पर दुःख की घड़ी में लेना बहुत कठिन होता है। उन्होंने अपने पिता की आंखों का दान करने का निर्णय लिया। परिवार के सभी सदस्यों ने इस पुनीत निर्णय पर सहमति जताई। परिजनों की सूचना मिलते ही नेत्रदान दल सक्रिय हुआ। रात के समय भी टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज लगभग दो घंटे के भीतर, रात्रि 11.38 बजे नेत्र उतक प्राप्त करने की



डॉ. अभिजीत जैन के नेतृत्व में टीम ने दिखाई तत्परता

इस पूरे मानवीय कार्य को सफल बनाने में नेत्रदान दल के टीम लीडर डॉ. अभिजीत जैन की भूमिका सबसे अहम रही। उनके नेतृत्व में डॉ. अभिषेक, डॉ. कंचन, नेत्र सहायक अधिकारी एवं सहायक नेत्रदान अधिकारी रमेश घृतकर की टीम ने पूरी प्रक्रिया को सम्मानजनक तरीके से पूरा किया। प्राप्त नेत्र उतकों को सुरक्षित रूप से सिम्स, बिलासपुर भेजने के लिए जयप्रकाश विश्वकर्मा ने विशेष सहयोग प्रदान किया, ताकि समय रहते किसी जरूरतमंद को कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जा सके। इस कार्य में राजमाता श्रीमती देवेंद्रकुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेघ्राम, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी और नोडल अधिकारी डॉ. रजत टोप्पो का भी निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग रहा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसे एक प्रेरणादायक पहल बताते हुए परिवार के निर्णय की सराहना की है। बता दें कि, भारत में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता के कारण अंधेरे में जीवन जीने मजबूर हैं, जबकि नेत्रदान से उन्हें नई रोशनी मिल सकती है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो कॉर्निया ब्लांइट व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती है। नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि अधिक उम्र, चरमा लगाना या मोतिव्याबिंद होने पर नेत्रदान नहीं हो सकता, जबकि चिकित्सकीय सच्चाई यह है कि ये सभी लोग भी संभावित नेत्रदाता हो सकते हैं। दान के बाद उतकों की गुणवत्ता की जांच विशेषज्ञ करते हैं और तय करते हैं कि वह प्रत्यारोपण योग्य है या नहीं।

नेत्रदान की प्रक्रिया और सावधानियां

नेत्रदान मृत्यु के बाद ही होता है, इसके लिए मृत्यु के 6 घंटे के भीतर नजदीकी आई बैंक या नेत्र विभाग को सूचना देना जरूरी है। यदि व्यक्ति ने जीवनकाल में सकल्य नहीं लिया है, तब भी निकट परिजन लिखित सहमति देकर दान करा सकते हैं। प्रशिक्षित दल द्वारा उतक लेने की प्रक्रिया सम्मानपूर्वक की जाती है, इससे चेहरे की बनावट विकृत नहीं होती और अंतिम संस्कार की परंपराओं में कोई बाधा नहीं आती। दल के आने तक मृतक की पलकों को धीरे से बंद रखें, बंद पलकों पर साफ नम रुई या गाँज रखें, सिर को थोड़ा ऊंचा रखें और पंखा बंद कर दें। नेत्रदान पूरी तरह स्वैच्छिक है। मानव नेत्रों की खरीद-विक्री कानूनन प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।

छ.ग.फ्रंटलाइन बलौदाबाजार-भाटापारा। सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। बिलासपुर से रायपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा के पास एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के समय बस में कुल 22 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया।

सुबह 5.30 बजे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक हादसा सोमवार 26 अक्टूबर सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा से पहले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक खराब होने से खड़ा था। सुरक्षा के लिए ट्रक के पास स्टॉपर भी लगाया गया था। इसी दौरान अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल कंपनी की बस क्रमांक सीजी 04 एनएम 0859 खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई।



बस में फंसे यात्रियों को गैस कटर से निकाला

हादसे के बाद कुछ यात्री बस में फंस गए थे। पुलिस और बचाव दल को उन्हें निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। सूचना मिलते ही बलौदाबाजार पुलिस, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को निकालकर शासकीय अस्पताल सिमगा भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बस अंबिकापुर से रायपुर आ रही थी।

महिला सैनिक ने लगाया प्रताड़ना का आरोप: सुरक्षा, विभागीय जांच व स्थानांतरण की मांग

महानिदेशक नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं को सौंपा शिकायत पत्र

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिला मुख्यालय में पदस्थ महिला सैनिक नीलम खलखो ने नगर सेना के दो कर्मचारियों के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और विभागीय स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने 19 अक्टूबर को नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं के महानिदेशक मुख्यालय नया रायपुर को लिखित शिकायत सौंपकर विभागीय जांच सुरक्षा और संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग की है। शिकायत में महिला सैनिक ने अखिलेश कुमार गुप्ता और अनिल कुमार यादव पर आरोप लगाए हैं। कहना है कि अखिलेश पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से जिला बलरामपुर में पदस्थ हैं। वहीं अनिल पिछले कई वर्षों से कार्यालयीन

शाखा में कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता ने विभागीय स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा है कि लंबे समय तक एक ही जगह और एक शाखा में पदस्थ रहने से अन्य कर्मचारियों को भी अवसर मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप महिला सैनिक ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों कर्मचारी मिलीभगत से कार्यालय में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। उन्होंने उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार गुप्ता पर पद का भय दिखाकर अधीनस्थ महिला सैनिकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने इन कथित कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए

निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला सैनिक का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। जांच और स्थानांतरण की मांग शिकायतकर्ता ने महानिदेशक से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत समिति का माध्यम से निष्पक्ष जांच कराई जाए। तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमाुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाए। इसके अलावा, उन्होंने शासन के स्थानांतरण नीति के अनुरूप दोनों कर्मचारियों को अनिल कुमार यादव को कार्यालयीन शाखा के स्थान पर जनरल ड्यूटी में पदस्थ करने की मांग की है। महिला सैनिक ने भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है।

अज्ञात कारणों से जहर सेवन की महिला की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की अज्ञात जहर सेवन से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम अजबनगर निवासी ढोला राम सेंटिंग मिस्त्री का काम करता है। मृतका लक्ष्मी से 20 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था लेकिन इनके संतान नहीं थे। 25 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे दोनों साथ में खाना खाए, और रात करीब 12 बजे तक मोबाइल देखने के बाद सो गए। 26 अक्टूबर को सुबह 5.30 बजे नींद खुली तो उसकी पत्नी उल्टी कर रही थी। पत्नी से पूछताछ करने पर उसने जहर सेवन करने की जानकारी दी। जहर सेवन करने का कारण नहीं बताई। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से उसे अजबनगर अस्पताल ले गए। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 26 अक्टूबर को सुबह 6.55 बजे उसकी मौत हो गई।

(बालाजी क्लीनिक)

मदरासी दवाखाना

Reg. No. Cg03026

ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं सूखी बवासीर, नासूर, भांदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षीर सूत्र से, एवं आंतों की धीमारियाँ जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुस रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अंबिकापुर मो. 90099-56307

डॉ. के.एम. राव

एम.एस.(आयु) शल्य

भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग

शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय-सीमा की बैठक : चक्रवात से निपटने की तैयारियों के साथ गिरदावरी और राज्योत्सव की हुई समीक्षा

★ शत-प्रतिशत त्रुटिरहित गिरदावरी के कलेक्टर ने दिये निर्देश ★ फसल रिकॉर्ड की सटीकता के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय, खसरो का करेंगे भौतिक सत्यापन
★ 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड पर मनाया जायेगा राज्योत्सव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आहूत की गई। बैठक में चक्रवात के प्रभाव से संभावित वर्षा, गिरदावरी कार्य तथा राज्योत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है तथा कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावित स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व अमले और आपदा प्रबंधन टीम को हर समय अलर्ट मोड पर रहकर जलभराव एवं बाढ़ की आशंका वाले संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावितों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाए।



को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रहने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित अवगत कराकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रहने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित

अवगत कराकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रहने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित

आपात स्थिति में डायल 112, जिला बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 07831-273002 अथवा स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने मौसम एवं राहत संबंधी जानकारी के लिए केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करने और अफवाहों से दूर रहने का आग्रह किया।

बैठक में गिरदावरी एवं ई-गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इसे शत-प्रतिशत त्रुटिरहित पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बहुस्तरीय सत्यापन की इस व्यवस्था से फसल रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित होगी और किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर मिल सकेगा। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार जिले में खसरो के भौतिक सत्यापन की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत जिला, अनुभाग एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को अलग-अलग प्रतिशत में खसरो की जाँच का दायित्व सौंपा गया है। जिला स्तरीय अधिकारी आवंटित ग्रामों में 1 प्रतिशत, 5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने प्रभार क्षेत्र में 5 प्रतिशत, 19 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 10 प्रतिशत तथा 13 कृषि विस्तार

अधिकारी और 23 राजस्व निरीक्षक 25-25 प्रतिशत खसरो का सत्यापन करेंगे। कलेक्टर ने सत्यापन कार्य समयबद्ध करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम व राजस्व अमले को प्राथमिकता के साथ कार्य को पूर्ण करने निर्देश दिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की बात कही। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में बताया गया कि जिले में राज्योत्सव का आयोजन 02 नवंबर को हाई स्कूल ग्राउंड में किया जाएगा। इस वर्ष की थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' रखी गई है, जिसके तहत लखपति दीदीयों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविकामूलक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी। कलेक्टर ने कार्य विभाजन के अनुसार तैयारियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, आर. एस. लाल बालेश्वर राम अभिषेक गुप्ता, सर्व एसडीएम व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

एसईसीएल की एक खदान और वर्कशॉप में हथियारबंद चोरों का धावा



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। एसईसीएल के बलरामपुर 10/12 अंडरग्राउंड खदान और विश्रामपुर स्थित एक्शन वर्कशॉप में हथियारबंद चोरों ने बीती रात धावा बोलकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। आरोप है कि बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धारदार हथियार दिखाकर बंधक बनाया और कीमती केबल लूटकर फरार हो गए। विश्रामपुर की वर्कशॉप में वारदात के दौरान एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया गया है। लगातार हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं से कोयलांचल के कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे बलरामपुर 10/12 अंडरग्राउंड खदान में 25 से 30 की संख्या में हथियारबंद लोग पहुंचे। आरोपियों ने सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को धारदार हथियार दिखाकर बंधक बना आर्मंड केबल के करीब 80 मीटर हिस्से को काटकर ले गए। बताया जा रहा है कि इसी रात करीब एक बजे बदमाशों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया है। एक ही रात में दो बार हुई

इस घटना ने खदान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर खदान के अलावा विश्रामपुर स्थित एक्शन वर्कशॉप को भी निशाना बनाया गया। यहां भी अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सुरक्षा विभाग दो कर्मचारियों जेबीआर व मुन्ना जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर धारदार हथियार से हमला करने उपरांत लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। यहां भी आरोपियों द्वारा हजारों रुपए के कीमती केबल लूट लिए हैं। वारदात के दौरान आरोपियों ने एक्सवेशन वर्कशॉप के समीप एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ा दी है। लगातार दो स्थानों पर हुई इन वारदातों से एसईसीएल के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं।

जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर कर्मचारी
कोयला खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगातार हो रही चोरी व लूटपाट की घटनाओं ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। ड्यूटी के दौरान हथियारबंद लोगों के हमले और बंधक बनाए जाने की आशंका के बीच कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए अब केवल मशीनों और उत्पादन से जुड़ी जिम्मेदारियाँ निभाना ही चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा रात्रिकालीन गस्त प्रभावी बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रबंधन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगी, ताकि वे भयमुक्त वातावरण में अपनी ड्यूटी कर सकें। ज्ञात हो कि लगातार हो रही इन वारदातों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कब और कितनी प्रभावी होगी, ताकि कोयला उत्पादन से जुड़े कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम न करना पड़े, यह भविष्य के गर्भ में है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पूर्व में भी बलरामपुर खदान में त्रिपुरा टैलरियां के जवानों व बदमाशों के बीच झड़प हुई थी, उसमें भी आरोपियों द्वारा जवानों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

बिश्रामपुर की पाखी को मिला छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन का अवार्ड

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। हुनर, मेहनत और लगन के दम पर विश्रामपुर की पाखी राय ने सौंदर्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। टूए कॉलोनी निवासी पाखी राय को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ उन्हें कंपनी की ओर से चार दिवसीय सिंगापुर यात्रा का अवसर भी मिला है। वह 24 अक्टूबर को सिंगापुर के लिए रवाना हो चुकी हैं।

जानकारी के अनुसार सितंबर माह में मुंबई के आईटीसी मराठा में आयोजित इस आयोजन में देशभर से करीब 700 ब्यूटीशियन और मेकअप आर्टिस्ट शामिल हुए थे। सौंदर्य एवं मेकअप के क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों के बीच पाखी राय को छत्तीसगढ़ की बेस्ट ब्यूटीशियन के रूप में चुना जाना विश्रामपुर के लिए गौरव की बात है। पाखी राय विश्रामपुर की टूए कॉलोनी में पाखी ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। उन्होंने अपने काम और कौशल के जरिए सौंदर्य सेवा के क्षेत्र में पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि ने उनके पेशेवर सफर को नई दिशा दी है। अवार्ड के

साथ कंपनी की ओर से उन्हें सिंगापुर आने-जाने और वहां ठहरने सहित चार दिनों का पैकेज दिया गया है। पाखी की इस सफलता से क्षेत्र



राय का यह सम्मान क्षेत्र में सौंदर्य व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं के लिए नई संभावनाओं और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा बन सकता है।

के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय स्तर पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मंच पर पहचान हासिल करना अन्य युवतियों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। पाखी के पति राजेश राय डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं। विश्रामपुर की इस उपलब्धि ने स्थानीय प्रतिभा और मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

बलरामपुर के हाईस्कूल ग्राउंड में 2 नवम्बर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा राज्योत्सव

गरिमामयी आयोजन के लिए अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राज्य शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में इस वर्ष जिला मुख्यालय बलरामपुर के हाईस्कूल ग्राउंड में 02 नवम्बर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम के सफल संचालन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन द्वारा नोडल, सहायक नोडल अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।



पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशुतोष चतुर्वेदी को सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलरामपुर श्री विवेक चन्द्रा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कानून एवं

शांति व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा कंट्रोल रूम की स्थापना की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को सौंपी गई है। इसके साथ ही

समतलीकरण, बैरीकेटिंग, मंच निर्माण, टेंट पंजाल, पर्याप्त रोशनी और ऐल.ई.डी. स्क्रीन की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और विद्युत यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन द्वारा 108 एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) सहित पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था तैनात रहेगी। इसके अलावा नगर पालिका बलरामपुर द्वारा पानी टैंकर और साफ-सफ़ाई, नगर सेना द्वारा अग्निशमन वाहन तथा जनसम्पर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार और मीडिया प्रबंधन का दायित्व निभाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मार्गदर्शन में सौंपे गए दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एनएच पर मौत को दावत दे रहे भूसे से ओवरलोड वाहन, दोपहिया सवारों की बढ़ी मुश्किलें

फटे बोरों से सड़क पर उड़ता भूसा बन रहा परेशानी का सबब, आंखों में कण जाने से हादसों का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 सहित क्षेत्र की अन्य सड़कों पर भूसे से लदे मालवाहक वाहन राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। वाहनों में असुरक्षित तरीके से भूसा लोड कर तेज रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। बोरों से निकलकर हवा में उड़ने वाला भूसा पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल राहगीरों की आंखों, नाक और मुंह में घुस रहा है। इससे वाहन चालकों का ध्यान भटकने और संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है। व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही कभी भी गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके बावजूद भूसे का असुरक्षित परिवहन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

राइस मिलों से पावर प्लांट तक पहुंचता है भूसा
जानकारी के अनुसार, राइस मिलों में धान की कुटाई के बाद निकलने वाले भूसे की पावर प्लांट संचालकों द्वारा खरीद की जाती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। सूरजपुर, अंबिकापुर सहित आसपास के जिलों से भूसे का परिवहन स्थानीय स्तर पर होने के साथ ही दूसरे जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी किया जाता है। इसके लिए ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों में भूसे को बोरों में भरकर गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। भूसे की ढुलाई से जुड़े इन वाहनों की आवाजाही राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य प्रमुख सड़कों पर लगातार बनी रहती है। लेकिन परिवहन के दौरान

सुरक्षा मानकों की अनदेखी राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। कई वाहनों में भूसे से भरे बोरों इस तरह रखे जाते हैं कि उनके फटने या उनसे भूसा बाहर निकलने की आशंका बनी रहती है। वहीं, बोरों की सिलाई कमजोर होने और उन्हें ठीक से नहीं बांधने के कारण रास्ते में

दिखाई देना मुश्किल हो सकता है। चालक की नजर सड़क से हटने या संतुलन बिगड़ने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यही स्थिति साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी पैदा करती है। खासकर व्यस्त मार्गों पर जब एक ओर भारी वाहन चल रहे हों



भूसा उड़ता रहता है। **हवा में उड़ता भूसा बन रहा दुर्घटना का कारण**
भूसे से लदे वाहनों के पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन की रफ्तार और हवा के दबाव के कारण बोरों से निकलने वाले भूसे के बारीक कण पीछे की ओर उड़ते हैं। ऐसे में बाइक या स्कूटी से सफर कर रहे लोगों की आंखों में अचानक भूसा चला जाता है। इससे कुछ पल के लिए सामने का रास्ता

और दूसरी ओर दोपहिया वाहन चालक उनसे आगे निकलने या सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रहे हों, तब उड़ता भूसा खरटे को और बढ़ा देता है। अचानक आंख में कण पड़ने पर चालक घबराकर वाहन मोड़ सकता है या अचानक ब्रेक लगा सकता है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने की आशंका भी बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर आवागमन के दौरान लोगों को भारी वाहनों के बीच सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में भूसे से

लदे वाहनों के पीछे चलना दोपहिया सवारों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है। कई बार वाहन चालक आगे चल रहे ट्रक से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के बावजूद हवा में उड़ते भूसे से बच नहीं पाते। इससे यात्रा के दौरान असुविधा होती है और दुर्घटना का डर बना रहता है। लोगों का कहना है कि माल का परिवहन करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए सड़क सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यदि बोरों की सही तरीके से सिलाई की जाए, फटे बोरों को बदला जाए और भूसे को सुरक्षित तरीके से बांधकर ढुलाई की जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, परिवहन के दौरान भूसा उड़ने से रोकने के लिए वाहनों पर उपयुक्त ढकाव की व्यवस्था भी जरूरी है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस और प्रशासन से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर असुरक्षित तरीके से भूसा लोड कर चलने वाले वाहनों की जांच की जानी चाहिए। जिन वाहनों से भूसा लगातार उड़ता रहता है, उनके संचालकों को सुरक्षित परिवहन के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही परिवहन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लोगों का मानना है कि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो किसी दिन उड़ते भूसे के कारण गंभीर सड़क हादसा हो सकता है।

28 अक्टूबर को विद्यालयों में मनाया जाएगा विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 28 अक्टूबर को विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को ई-कचरे के दुष्प्रभावों तथा उसके सुरक्षित संग्रहण एवं

निपटान के प्रति जागरूक करना है।सूरजपुर जिले में कलेक्टर रेना जामिल, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा मनोज साहू के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

27 अक्टूबर तक होगी पूर्व तैयारी

कार्यक्रम की प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में 21 से 27 अक्टूबर तक पूर्व तैयारी एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस दौरान

शिक्षक विद्यार्थियों और अभिभावकों को ई-कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों को अपने घरों में अनुपयोगी पड़े इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों की पहचान करने तथा उन्हें सामान्य कचरे में फेंकने के बजाय सुरक्षित तरीके से एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पुराने मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर, केबल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर तथा अन्य अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्यालय में एकत्रित किया जाएगा।



इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में ई-कचरा संग्रहण कॉर्नर बनाया जाएगा, जहां एकत्रित सामग्री को सुरक्षित रखा जाएगा। बाद में इसे

ई-कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती

आज के डिजिटल युग में ई-कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यदि इसका निपटान उचित तरीके से नहीं किया जाए, तो यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ई-कचरे में सीसा, पारा, कैडमियम तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। इन्हें खुले में फेंकने, जलाने या अनुचित तरीके से तोड़ने पर विषैले तत्व मिट्टी और पानी को

प्रदूषित कर सकते हैं।ई-कचरे को जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ा सकता है तथा दूषित मिट्टी और पानी का असर खाद्य श्रृंखला तक पहुंच सकता है। वहीं, लापरवाही से रखी गई क्षतिग्रस्त बैटरियों में रिसाव, शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी हो सकता है।दुसरी ओर, ई-कचरे में मौजूद तांबा, एल्युमिनियम और अन्य उपयोगी धातुओं का अधिकृत प्रक्रिया से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है।

28 अक्टूबर को होगी जागरूकता गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं

विशेष ई-कचरा प्रबंधन दिवस के अवसर पर विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान जागरूकता संवाद आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, नारा लेखन और चित्रकला जैसी रचनात्मक गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

साइबर सुरक्षा की बारीकियों से रूबरू हुए कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, साइबर सेल अंबिकापुर में लिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा तथा साइबर अपराधों की रोकथाम संबंधी व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने साइबर सेल अंबिकापुर का शैक्षणिक भ्रमण कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा की अनुमति तथा प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा एवं विभागाध्यक्ष सुश्री मोनिका खेस के मार्गदर्शन में रसाइबर सुरक्षा जागरूकता: साइबर सेल अंबिकापुर में डिजिटल सुरक्षा और कानून का व्यावहारिक अनुभवरूप विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समन्वय सहायक प्राध्यापक उमेश पांडेय,



विनोद कुमार गुप्ता एवं अनुभव श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान रेंज साइबर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल अपराधों की पहचान, अपराध अनुसंधान की आधुनिक तकनीकों एवं बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

एआई आधारित निगरानी प्रणाली का प्रदर्शन

साइबर विशेषज्ञ अधिकारी गणेश कदम ने विद्यार्थियों को शहर की आधुनिक निगरानी व्यवस्था, सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी

कैमरा प्रणाली, फेस डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन तथा आपराधिक गतिविधियों की निगरानी की तकनीकों से अवगत कराया। उन्होंने साइबर सेल में उपयोग किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सिस्टम का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।

केस स्टडी के माध्यम से बताएं बचाव के उपाय

उपनिरीक्षक अभय तिवारी ने विभिन्न साइबर अपराधों के उदाहरण एवं केस स्टडी के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, वित्तीय

धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, नेटवर्किंग एवं सर्विलांस सिस्टम की सहायता से अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाता है। विद्यार्थियों को सॉदिध लॉक एवं कॉल से सावधान रहने तथा धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

डायल 112 एवं हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

कंट्रोल रूम में डायल 112 के अधिकारियों ने आपातकालीन सहायता सेवा की कार्यप्रणाली, यातायात नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए 112 इंडिया ऐप एवं लोकेशन आधारित सुविधाओं के उपयोग के बारे में समझाया।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

26वीं राज्यस्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, ओवरऑल चैंपियन बना रायपुर

अंबिकापुर। खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 का समापन समारोह आज मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती मंजूषा भगत के आतिथ्य में संपन्न हुआ। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 404 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समारोह में महापौर ने विभिन्न खेल विधाओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि जीवन में हार-जीत लगी रहती है। खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर खेलना अपने आप में बड़ी



उपलब्धि है। आप सभी अपनी प्रतिभा और काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंचें। हार और जीत का अंतर किसी की काबिलियत को कम नहीं करता। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता के लिए प्रेरित किया।

विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों के अनुसार बैडमिंटन 17 वर्ष

सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। फुटबॉल 19 वर्ष बालक वर्ग में बस्तर ने प्रथम, सरगुजा ने द्वितीय और दुर्ग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।सॉफ्ट टेनिस की विभिन्न आयु वर्गों की स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 14 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, रायपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय रहा। 17 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, रायपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय रहा, जबकि 19 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और रायपुर तृतीय स्थान पर रहा। सॉफ्ट टेनिस 14 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और सरगुजा तृतीय स्थान पर रहा। 17 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, बिलासपुर द्वितीय और दुर्ग तृतीय स्थान पर रहा। वहीं 19 वर्ष बालिका वर्ग में रायपुर प्रथम, दुर्ग द्वितीय और बिलासपुर तृतीय स्थान पर रहा।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए निर्देश

चक्रवात और भारी बारिश की चेतावनी पर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 नवंबर को

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रताप विजय खेस, नगर निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, जन



चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों का गंभीरता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत वसूली प्रकरणों, अपूर्ण कार्यों, जाति प्रमाणपत्र एवं जन्म प्रमाणपत्र निर्माण, मुआवजा प्रकरणों सहित अन्य विषयों पर भी समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का जिला आगमन प्रस्तावित है, जिसके लिए संबंधित

अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मौसम विभाग की चेतावनी पर अलर्ट रहने के निर्देश

मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवात संबंधी चेतावनी एवं प्रदेश में संभावित भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के

कर राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने, एसडीआरएफ, होमगार्ड को तैयार रखने तथा जलाशयों और बांधों के जलस्तर की सतत निगरानी के निर्देश दिए।

राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 नवंबर को

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय राज्योत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवागमन, स्टॉल, साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, मंच एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

कर राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने, एसडीआरएफ, होमगार्ड को तैयार रखने तथा जलाशयों और बांधों के जलस्तर की सतत निगरानी के निर्देश दिए।

राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 2 नवंबर को

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय राज्योत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवागमन, स्टॉल, साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, मंच एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

सरगुजा में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान, अंबिकापुर से रायपुर-जगदलपुर होते हुए हैदराबाद तक उड़ान शुरू

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के बाद अब अंबिकापुर से रायपुर और रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद तक हवाई यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। इस हवाई सेवा के शुरू होने से सरगुजावासियों को आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा और प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस मार्ग पर एटीआर-72 विमान के माध्यम से हवाई सेवा उपलब्ध कराने की पहल के लिए एलायंस एयर का आभार जताया गया है। नई सेवा की शुरूआत को सरगुजा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए



क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं।

मंगलवार को पहली उड़ान से रवाना होंगे जनप्रतिनिधि

हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर संबंधित जनप्रतिनिधि ने मंगलवार को इसी फ्लाइट से अंबिकापुर से रायपुर के लिए रवाना होने की जानकारी दी है। इससे नई हवाई सेवा की शुरूआत को लेकर क्षेत्र में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।

लंबे समय से थी मांग

अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू होना सरगुजा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है। इस सुविधा से यात्रियों को सड़क मार्ग पर लम्बे वाले समय से राहत मिलेगी। साथ ही, कारोबार, पर्यटन, चिकित्सा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों की भी लाभ मिलेगा। अंबिकापुर को रायपुर, जगदलपुर और हैदराबाद से जोड़ने वाली यह हवाई सेवा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

संभाग स्तरीय फुटबॉल मुकाबले मे सरगुजा इलेवन और परसोड़ी सेमीफाइनल में

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। गांधी स्टेडियम में चल रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले जा रहे सुपर लीग मुकाबलों में दो अहम मैच खेले गए, जिनके बाद सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई। फुटबॉल प्रेमियों की भारी मौजूदगी के बीच खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। सुपर लीग का पहला मैच रेलवे कर्जी और परसोड़ी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने मैदान पर संतुलित और रक्षात्मक खेल दिखाया। प्रथम हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर



कई हमले किए, अच्छे पास और तालमेल देखने को मिला, लेकिन गोलकीपरो की मुस्तेदी और डिफेंस की मजबूती के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी मैच का रोमांच बरकरार रहा, दोनों टीमों ने गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन स्कोर बोर्ड 0-0 ही रहा। नियमानुसार

दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया गया। इस अंक के साथ परसोड़ी टीम ने अंक तालिका में कुल 5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दिन का दूसरा और सबसे रोमांचक मैच सरगुजा इलेवन और मेंडरा के बीच खेला गया। इस मैच में

सरगुजा इलेवन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। प्रथम हाफ में सरगुजा इलेवन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और एकतरफा खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने लगातार हमले करते हुए विपक्षी डिफेंस को पूरी तरह से बिखेर दिया और 5 गोल दागकर 5-0 की बड़ी बढ़त बना ली। दर्शकों ने हर गोल पर तालियों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। दूसरे हाफ में मेंडरा की टीम ने वापसी की कोशिश की और दोनों टीमों ने तेज और रोमांचक खेल दिखाया। दोनों तरफ से लगातार हमले हुए, कई सुनहरे मौके भी बने, लेकिन दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। अंततः सरगुजा इलेवन ने 5-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर

सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष जीतेन्द्र गुप्ता जीतु उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैच के निर्णायक के रूप में ललित किशोर, सचिन, सुशील, शिव बहादुर लाम्बा ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर आयोजन समिति के सचिव दीपक कुजूर, कमलेश किस्मोद्वा सहित कई खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज प्रतियोगिता का प्रथम सेमीफाइनल मैच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला बलसेड़ी और परसोड़ी के बीच होगा। दोनों टीमों फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय (घंघरी) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ ओपन काउंसिलिंग में प्राप्त आवेदनों के आधार पर चतुर्थ चयन सूची जारी कर दी गई है। चयन सूची मेरिट क्रम के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशानुसार चयनित विद्यार्थियों को 30 अक्टूबर तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं में प्रथम

श्रेणी (60 प्रतिशत) से उत्तीर्ण अंकसूची, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीडित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश की पात्रता होने पर दो दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) एवं जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित विद्यार्थियों को आवंटित प्रयास आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश लेना होगा। विद्यालय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

आंगनबाड़ी सहायिका मर्ती हेतु अंतिम सूची जारी, 5 नवम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

अम्बिकापुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) में रिक ऑगनबाड़ी सहायिका के 01 पद आंगनबाड़ी केन्द्र खालपारा चार्ड क्रमांक 06 में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी अंनतिम सूची प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट द्वारा आनलाईन दावा आपत्ति 26 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक आमंत्रित की गई है। निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

फ्रांस में अंजाम दी गई बेरोक-टोक अग्निकांडों और लूटपाट की वारदातों से समूची दुनिया स्तब्ध होकर रह गई है। आखिरकार इस विनाशकारी हिंसक आंदोलन की बुनियाद में कौन से प्रमुख कारण विद्यमान रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इसके पीछे अल्ट्रा लेफ्ट ताकतों को जिम्मेदार मानते हैं। इस हिंसक विरोध आंदोलन की कड़ियां भारत तक जुड़ गई हैं। इसमें विदेशी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल सरकारों की नीतियों का विरोध करना है या चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना भी है? इन सवालों ने हाल ही में अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज की एक खोजी रिपोर्ट के बाद चर्चा का रूप ले लिया है। यूरोप के हिंसक प्रदर्शनों से भारत को सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों के भरोसे, संस्थाओं की निष्पक्षता, शांतिपूर्ण असहमति की स्वतंत्रता और कानून के समान अनुपालन में निहित है। भारत ने जिस तरह से हालिया प्रदर्शनों को नियंत्रित किया है, उस पर टिप्पणी को लेकर मानवाधिकार संगठनों का छद्म छलावा प्रदर्शित होता है। *इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

फ्रांस से उठा यूरोप में फैला हिंसक तूफान



विवेचन

प्रभात कुमार राय

विदेश मामलों के जानकार

16 सितंबर 2026 का दिन

था। पेरिस से तकरीबन 12

किलोमीटर की दूरी पर

स्थित है गांव का एक हाई

स्कूल, जहां से फ्रांस में

विद्यार्थियों के वर्तमान

आंदोलन की शुरुआत हुई।

विद्यार्थियों की दीर्घ काल से

सरकार से मांग रही है कि

उनके स्कूल में पर्याप्त

संख्या में टीचर्स नहीं हैं और

स्कूल की हालत बहुत जर्जर

है। आखिरकार विद्यार्थियों

द्वारा अपने स्कूल के दरवाजे

बंद कर दिए गए। एक स्कूल

से शुरू हुआ विद्यार्थी

आंदोलन आसपास के

स्कूलों में तेजी के साथ फैल

गया, क्योंकि तकरीबन

सभी स्कूलों के हालात बहुत

ही खराब रहे हैं। इन स्कूलों

के अध्यापक भी विद्यार्थियों

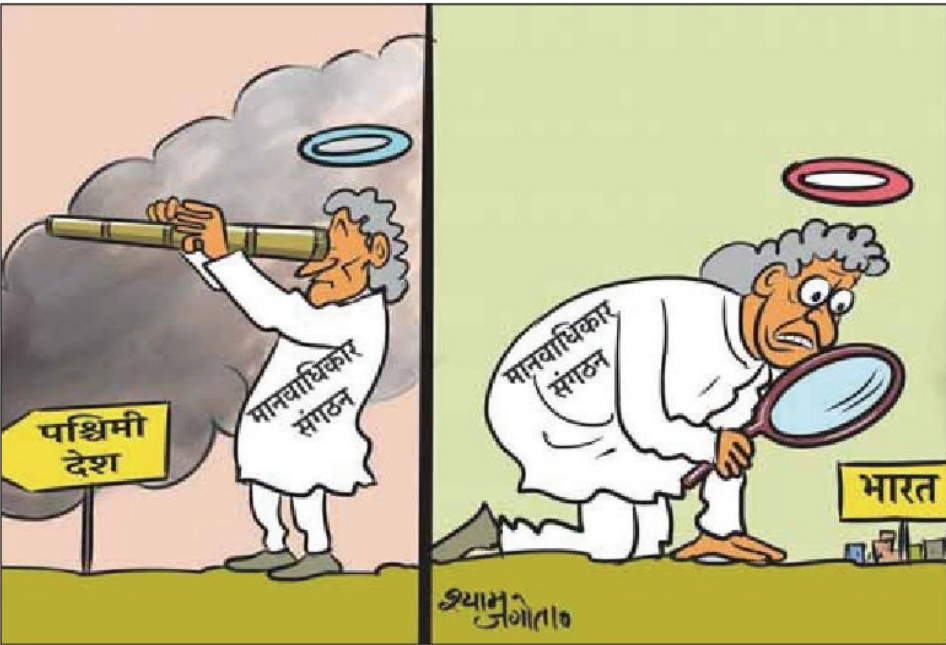
के आंदोलन में शामिल हो

सं पूर्ण दुनिया स्तब्ध होकर रह गई है, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस और आसपास के नगरों की सार्वजनिक इमारतों से उठती हुई विनाशकारी अग्नि ज्वालाओं का दुनिया ने दीदार किया। फ्रांस में अंजाम दी गई बेरोक-टोक अग्निकांडों और लूटपाटों ने फ्रांस का ही नहीं, वरन् समूची दुनिया के खिल को हिला कर रख दिया है। इतहा तो तब हो गई, जब पेरिस से उठा हिंसककारी आंदोलन अल्बानिया, इटली, स्पेन, सर्बिया आदि यूरोप के अनेक देशों में भी फैल गया है। आखिरकार इस विनाशकारी हिंसक आंदोलन की बुनियाद में कौन से प्रमुख कारण विद्यमान रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ्रांस में अंजाम दी गई हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। ट्रंप ने अपने मतदाताओं को खबरदार करते हुए फरमाया कि बस आप फ्रांस को देख लीजिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्रांस का पेरिस नगर बहुत जल्दी एक मुस्लिम बहुल नगर बन जाएगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बेहदा और एकदम गलत बताया। यह कहना कि फ्रांस के इस्लामी प्रवासियों की भारी भीड़ ने फ्रांस पर हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप की यह बात पूरी तरह से बेबुनियाद और सरास झूठ है। मैक्रों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के लिए हमारे देश के विद्यार्थी आंदोलन के विषय में एकदम झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस में हिंसक वारदातों के लिए फ्रांस की अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें जिम्मेदार हैं। 16 सितंबर 2026 का दिन था। पेरिस से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव का एक हाई स्कूल, जहां से फ्रांस में विद्यार्थियों के वर्तमान आंदोलन की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों की दीर्घ काल से सरकार से मांग रही है कि उनके स्कूल में पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं हैं और स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। आखिरकार विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक स्कूल से शुरू हुआ विद्यार्थी आंदोलन आसपास के स्कूलों में तेजी के साथ फैल गया, क्योंकि तकरीबन सभी स्कूलों के हालात बहुत ही खराब रहे हैं।

6 माह बाद फ्रांस में होंगे चुनाव

ये सभी मेहनतकश किसानों और मजदूरों के बच्चों के सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों के अध्यापक भी विद्यार्थियों के आंदोलन में शामिल हो गए और उनके मेहनतकश मा-बाप भी धीमे-धीमे इसमें शामिल होने लगे। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों में हाई स्कूल के विद्यार्थियों का आंदोलन बहुत तेजी के साथ संपूर्ण फ्रांस



फ्रांस में आपातकाल घोषित होने के आसार

वामपंथी शक्तियां बेहद खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई को इस अत्यंत हिंसक आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। 17 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रदर्शन स्थल प्लाजा द ला रिपब्लिक पर तकरीबन आठ लाख लोग वसूत बढते हुई महंगाई और अस्थी सरकारों शिक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। किंतु काले कपड़ों में कुछ नकाबपोश एक्टिविस्टों के एक गिरोह के आने के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन अत्यंत हिंसक हो उठा। अभी तक तकरीबन पांच हजार उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री लेकॉर्नो द्वारा म्यानक हिंसा के लिए अल्ट्रा लेफ्ट के एक्टिविस्टों को दोषी करार दिया गया है। म्यानक हिंसा के तांडव तत्पश्चात राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा बयान जारी किया गया कि फ्रांस में आपातकाल नाफिज किया जा सकता है। फ्रांस के गृहमंत्री लारा ब्युजेन ने कहा है कि पेरिस के अनेक नगरों में हिंसक विरोधी प्रदर्शन के बाद हालात दंगा नियंत्रक पुलिस के नियंत्रण से बाहर निकल गए। गृहमंत्री द्वारा भी हिंसक दंगों के लिए अल्ट्रा लेफ्ट के एक्टिविस्टों को दोषी करार दिया गया है। फ्रांस में प्रदर्शनों का दौर जारी है। राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है।

राजनीतिक दल भी शामिल

फ्रांस के राजनीतिक दल भी इस हिंसक बन चुके आंदोलन में शामिल होकर अपने-अपने लिए सुखियां बटोरने की होड़ में जुटे हुए हैं। इस वक्त फ्रांस में हिंसक तांडव अत्यंत तीव्रता के साथ बढ रहा है। फ्रांस के आंदोलन में जारी म्यानक आगजनी और हिंसक तांडव फ्रांस के वर्तमान इतिहास में सबसे खराब

मैक्रों की नीतियों की आलोचना

कहीं भी फ्रांस की दंगा नियंत्रक पुलिस द्वारा हिंसक उपद्रवियों पर गोलियां नहीं दागी गईं। सिर्फ एक व्यक्ति के हतहत होने का समाचार है। फ्रांस के गृहमंत्रालय के अनुसार 17 अक्टूबर को लगभग एक हजार पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए। जिसमें सात की हालत बहुत गंभीर है। विश्व पटल पर प्रख्यात

एकांगी दृष्टिकोण के असर में मानवाधिकार संगठन



दिव्या

उमेश चतुर्वेदी

राजनीतिक समीक्षक

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब भारतीय सुरक्षा बलों और सरकार पर उसकी कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाया हो। कश्मीर घाटी में आतंकी खून बहाते रहे, तब मानवाधिकार संगठनों ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब भी इन आतंकियों के खिलाफ भारतीय बलों ने कड़ी कार्रवाई की, उनके समर्थकों को सीखवों के पीछे डालना शुरू किया, मानवाधिकार संगठनों को उनके मानवाधिकार की रक्षा होने लगी। ऐसे में हालिया आंदोलनों के दौरान भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठन सवाल नहीं उठाते तो ही हैरत होती। नीट परीक्षा के खिलाफ कॉन्फेरोज जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उसके खिलाफ अगर सुरक्षा बल, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो बाद में वे ही सवालों के घेरे में होते। संसद से महज दो सी मीटर की दूरी पर जिस तरह आंदोलन में शामिल असामाजिक और अराजक तत्व उकसाऊ कार्रवाई कर रहे थे, उसमें पुलिस और प्रशासन के पास बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। सोचिए अगर, उस दिन उपद्रवी संसद में घुस जाते और भारतीय संसद के साथ कुछ वैसी ही अनहोनी होती, जैसा अभी हालिया प्रदर्शन के दौरान अल्बानिया में हुआ है तो क्या भारतीय लोकतांत्रिक समाज उसे स्वीकार कर पाता? भारत में हालिया आंदोलनों की शुरूआत नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में हुई। इसी दौरान अचानक से एक नई पार्टी 'कॉन्फेरोज जनता पार्टी' बनी और उसके बैनर तले देशभर के युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाल दिया। गगनादित आंदोलनों के जरिए लोक अपना गुस्सा निकालकर शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लोक में अराजक तत्व भी होते हैं और वे आंदोलनों की ताक में रहते हैं। लोकतांत्रिक आंदोलनों में वे मौका पाते ही घुस जाते हैं और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। कॉन्फेरोज जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद में मार्च में ऐसा ही हुआ। कॉन्फेरोज जनता पार्टी के संसद मार्च में ऐसा ही हुआ। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेकने में जेब्रुन छात्रों की संख्या कम, अराजक और असामाजिक तत्वों की संख्या ज्यादा रही। इस तथ्य को सुरक्षा बलों ने भी स्वीकार किया है। सुरक्षा बलों के नरम स्वभाव के पीछे आंदोलन में शामिल युवा रहे। सुरक्षा बलों और प्रशासन को लगता था कि अगर युवाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन एसआईआर के खिलाफ और मुख्य निवाचन आयुक्त हानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की ओर बढ़ा, इसने राजनीतिक रंग ले लिया। निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन में छात्र कहीं नक्यय में जाते हुए दिखे और गोचें पर कांग्रेस की अनुअर्गई में विपक्षी दल दिखे। सुरक्षा बलों ने अपना संयम बनाए रखा। चुनाव आयोग पर प्रदर्शन के लिए संसद से निकले विपक्षी सांसदों और उनके समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। लोगों को जुटने से रोकना गया। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोगों के साथ हथपाई भी हुई हो, किसी को चोट लगी हो। आंदोलन में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। दुनिया की कोई भी सरकार आंदोलनकारियों का फूलों से स्वागत नहीं करती। सरकार और सुरक्षा बलों ने जिस तरह संयम दिखाकर सिर्फ हिरासत में लेकर आंदोलन को हिंसक होने से रोकने में सफलता पाई, उसका समाज के एक बड़े हिस्से ने स्वागत भी किया है। आंदोलनकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता को आसानी से म्यानप का एजेंट कह जा सकता है। लेकिन त्योहारी मौसम में कारोबारी नुकसान पहुंचा रहे कर्नाट पैसे के कारोबारियों का आंदोलन के विरोध में खड़ा होना मामूली बात नहीं है। इससे साफ हुआ कि जनता भी ऐसे आंदोलनों की परख नहीं कर रही। दुर्भाग्य यह है कि चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर द्यूकनराइट वाच, या संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति, उन्होंने इस पूरे घनाकन, सुरक्षा बलों के संयम, प्रधानमंत्री को दी गई गोलियों की ओर ध्यान नहीं दिया। एसआईआर और नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुआ आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति एवं विशेषज्ञों का चित्त जताना मामला एक एक तरफा संहान लेना है। द्यूकन राइट्स वॉच और संयुक्त राष्ट्र

द्यूकन राइट्स वॉच व संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएनसीडीआरडी ने अपनी रिपोर्टों में, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने और उनके खिलाफ नफरती भाषणा आदि का आरोप लगाया है।

गए और उनके मेहनतकश मा-बाप भी धीमे-धीमे इसमें शामिल होने लगे। कुछ ही दिनों में आंदोलन तेजी से फ्रांस में विस्तारित हो गया।

में विस्तारित हो गया। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के आंदोलन में फ्रांस की युनिवर्सिटियों के विद्यार्थी भी शामिल होने लगे और अमीरों के स्कूलों के विद्यार्थी भी इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए सड़कों पर आ गए। फ्रांस के मजदूरों की ट्रेड यूनियंस भी आंदोलन में शामिल हो गईं। विद्यार्थी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए दंगा नियंत्रक पुलिस फोर्स भेजी गईं। क्योंकि ये कहीं-कहीं आंदोलन हिंसक होने लगा था। उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष 6 महीनों के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला वामपंथी और दक्षिणपंथी उन्मीदवारों के बीच होगा है। राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार हैं प्रवासी विरोधी अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी मरैन ले पेन और पूंजीवाद के घोर विरोधी वामपंथी उन्मीदवार जीन ल्यूक मेलेचोन।

घटनाओं में से एक रहा है। फ्रांस में हिंसक तनाव राजनीति के गलियारों से लेकर सड़कों तक तांडव करत नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मुख्यमन्त्री एलिसे पैलेस के अनुसार देश के गृहमंत्री लॉरेंट ब्युजेन ने अपना त्यागपत्र देते की पेशकश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया और फरमाया कि फ्रांस की सड़कों को सुरक्षित बखाने के लिए और म्यानक हिंसा के दोषी अपराधियों को इलाफ के कठोरे में लाने के लिए सख्त तौर तरीके अक्षिधार किए जाएं। फ्रांस की हुकुमत के मुताबिक तकरीबन दो हजार दुकानों और व्यवसायों में आगजनी और लूटपाट अंजाम दी गई है। दंगा नियंत्रक पुलिस द्वारा हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वाटर कैनन की बीछरें की गईं। जगह-जगह पर पुलिस को उपद्रवी भीड़ को लाठियों से पीटते हुए देखा गया।

पर्यटक सिटी ऑफ लाइट पेरिस में आजकल दुर्भाग्यवश अंधकार छाया हुआ है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा पेरिस के कुछ हिस्सों में और कुछ अन्य शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने राष्ट्र की संवैधानि करते हुए राष्ट्रीय एकता और शांति बनाए रखने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्वारा फ्रांसीसी जनता को आश्वासन देने का प्रयास किया गया कि हिंसा के दोषियों को कानून द्वारा कठोरतापूर्वक दंडित किया जाएगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की नीतियों की जमकर आलोचना भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके शासनकाल के दौरान फ्रांस के हालात बढ से बढतर होते गए हैं। फ्रांस की दक्षिणपंथी शक्तियां मध्यमार्गी राष्ट्रपति मैक्रों की फ्रांसीसी हुकुमत को उसकी विनाशकारी प्रवासी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं

की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएनसीडीआरडी ने अपना रिपोर्ट में, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने और उनके खिलाफ नफरती भाषणा आदि का आरोप लगाया है। ये संघर्ष विदेशी अत्याचन किमगन अधिपक्षम यानी एफसीआईआर और कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों, मसलान यूरोपीय के दुर्कप्रयोग का भी भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। मानवाधिकार संगठन चाहे जो भी कहें, लेकिन विशेषकर राजधानी दिल्ली में जिस तरह सुरक्षा बलों ने खुद पर हुए हमलों के खानजूद जवाबी कार्रवाई में संयम दिखाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। पश्चिमी समाज और उसके कथित मानवाधिकार संगठनों का नजरिय विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए एकतरफा ही रहा है। बेशक भारत आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन अब भी भारत को लेकर उनकी सोच पुरानी ही है। जिसे अब देश की अधिसंख्य जनता समझने लगी है, इसीलिए अब ऐसे आरोपों और पर्यवेक्षणों से भारतीय मानस उस तरह प्रभावित नहीं होता, जैसा अतीत में होता रहा है।

विरोध-प्रदर्शनों के पीछे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क



रिपोर्ट

विवेक शुक्ला

वरिष्ठ पत्रकार

दुनिया के अलग-अलग देशों में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के बीच क्या कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी काम कर रहा है? क्या कुछ विदेशी संगठन स्थानीय असंतोष को साझा राजनीतिक अभियान का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इन गतिविधियों की नीतियों का विरोध करना है या चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना भी है? इन सवालों ने हाल ही में अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज की एक खोजी रिपोर्ट के बाद चर्चा का रूप ले लिया है।

रिपोर्ट में फ्रांस में छात्र आंदोलनों और भारत में हुए राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के बीच कथित संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें इंडियन एलायंस पेरिस (आईएपी) नामक संगठन का भी जिक्र है। हालांकि, रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। फॉक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विभिन्न देशों में सक्रिय 101 संगठन विरोध-प्रदर्शनों के आयोजन, उनके प्रचार या उनके संदेशों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में जुड़े हुए हैं। इस कथित नेटवर्क में वामपंथी और समाजवादी समूहों, छात्र संगठनों, श्रमिक संघों, मीडिया मंचों तथा राजनीतिक सक्रियता से जुड़े संगठनों की भूमिका है। इस दावे का आधार यह है कि अलग-अलग देशों में होने वाले आंदोलनों के बीच सोशल मीडिया संदेशों, सार्वजनिक बयानों, संगठनों के आपसी संपर्क और एकजुटता अभियानों के माध्यम से संबंध बनते दिखाई देते हैं। फ्रांस में छात्रों के आंदोलनों और भारत में मुख्य निवाचन आयुक्त हानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों का संदर्भ इसी सिलसिले में सामने आया है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या विरोध-प्रदर्शनों के बीच वैचारिक समानता, साझा संदेश या अंतरराष्ट्रीय समर्थन अपने आप में किसी गुप्त साजिश का प्रमाण है? ऐसे संबंध किसी संगठित राजनीतिक अभियान की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं,

लेकिन उनसे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि संबंधित संगठन किसी चुनी हुई सरकार को गिराने या विरोध-प्रदर्शन शुरू कराने की योजना चला रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में इंडियन एलायंस पेरिस को फ्रांस में सक्रिय भारतीय मूल के छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों से जुड़ा संगठन बताया गया है। इस संगठन ने फ्रांस प्रदर्शनों से संबंधित संदेशों को सोशल मीडिया पर साझा किया और भारत तथा फ्रांस में युवाओं के आंदोलनों के बीच समानताओं को रेखांकित किया। रिपोर्ट में न्यूयॉर्क स्थित पीपुल्स फोरम और

अथवा सरकार गिराने की साजिश का प्रमाण नहीं है। इसके लिए वित्तीय लेन-देन, निर्देशों, संगठनात्मक नियंत्रण और वास्तविक गतिविधियों से जुड़े ठोस साक्ष्यों की जरूरत होती है। इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू विदेशी वित्त पोषण है। रिपोर्ट में अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम और उनसे जुड़े कुछ संगठनों का उल्लेख किया गया है। इस विषय पर विचार करते समय लोकतंत्र के दो बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। पहला, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए विदेशी धन, गुप्त



इंडियन एलायंस पेरिस का नाम सामने आने से भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हुई है। हालांकि, किसी संगठन का दूसरे संगठनों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना, किसी आंदोलन का समर्थन करना अपने आप में गैरकानूनी गतिविधि अथवा सरकार गिराने की साजिश का प्रमाण नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मंच प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का भी उल्लेख किया गया है। इन संगठनों और कुछ अन्य समूहों के बीच संपर्कों की आधार बनाकर यह सवाल उठाया गया है कि क्या अलग-अलग देशों के आंदोलनों को साझा राजनीतिक दिशा देने की कोशिश हो रही है। इंडियन एलायंस पेरिस का नाम सामने आने से भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हुई है। हालांकि, किसी संगठन का दूसरे संगठनों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना, किसी आंदोलन का समर्थन करना या सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना अपने आप में गैरकानूनी गतिविधि

निर्देशों या गैरकानूनी हस्तक्षेप का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। यदि ऐसे हस्तक्षेप के प्रमाण मिलते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। आवश्यक है कि किसी भी रिपोर्ट में किए गए दावों की जांच दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड, प्रत्यक्ष साक्ष्यों और संबंधित संगठनों के जवाबों के आधार पर की जाए। यह भी देखना चाहिए कि संगठनों के बीच संबंध केवल वैचारिक समर्थन और प्रचार तक सीमित हैं या वास्तव में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए निर्देशित गतिविधियां संचालित की गई हैं।



मंथन

योगेश कुमार सोनी

स्वतंत्र पत्रकार

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज बुलंद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जब सरकारें जनभावनाओं को अनसुना करती हैं, नीतियों से असंतोष बढ़ता है या लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तब सड़कों पर उतरकर विरोध करना स्वाभाविक है। जन वही विरोध हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से टकराव का रूप ले लेता है, तो सवाल केवल प्रदर्शनकारियों के उद्देश्यों का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और कानून के शासन का भी बन जाता है। यूरोप के विभिन्न देशों में समय-समय पर हुए हिंसक प्रदर्शनों से भारत को भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हालांकि यूरोप एक समान राजनीतिक या सामाजिक इकाई नहीं है।

फ्रांस में पेंशन सुधारों के विरोध, किसानों के आंदोलन, ब्रिटेन में दंगों और अन्य देशों में आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों की परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं। इसलिए हर घटना को एक ही नजरिये से देखने के बजाय उसके कारणों और परिणामों को समझना आवश्यक है। हिंसक प्रदर्शनों का पहला सबक यह है कि जन-असंतोष को समय रहते समझना और उसका समाधान करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, किसानों की समस्याएं, सामाजिक भेदभाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसे मुद्दे लोगों में नाराजगी पैदा कर सकते हैं। यदि नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहरा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण है। यहां भाषाई, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और आर्थिक विविधता के कारण अलग-अलग वर्गों की अपेक्षाएं भी अलग हैं। सरकारों को चाहिए कि वे नीतियों के निर्माण और

क्रिया-न्ययन में जनसंवाद को प्राथमिकता दें। समय पर संवाद और शिकायतों का समाधान कई बार उस स्थिति को पैदा होने से रोक सकता है, जिसमें सामान्य विरोध उग्र हो जाता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर हिंसक घटना का कारण सरकारी नीतियों की विफलता ही नहीं होता। अफवाहें, संगठित उकसावे, आपराधिक तत्व और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि नागरिक सरकार की नीतियों से असहमति जता सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन,

दुकानदारों की आजीविका पर असर पड़ता है और भय का वातावरण बनता है। सोशल मीडिया जनसमस्याओं को सामने लाने, लोगों को संगठित करने और प्रशासन तक शिकायतें पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। लेकिन यही माध्यम भ्रमक सूचनाओं, पुराने वीडियो को नई घटना बताकर प्रसारित करने, नफरत फैलाने और भीड़ को उकसाने का जरिया भी बन सकता है। यूरोप और भारत, दोनों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिना पुष्ट की गई खबरें आग में ही डालने का



यूरोप की हिंसक घटनाएं याद दिलाती हैं कि जब विरोध की सीमा टूटती है, तो सबसे अधिक नुकसान अक्सर उन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हितों की रक्षा का दावा किया जाता है। कारोबार प्रभावित होता है, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, छोटे दुकानदारों की आजीविका पर असर पड़ता है।

धरना, जुलूस और सार्वजनिक बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। लेकिन किसी नीति का विरोध करने का अधिकार सार्वजनिक संपत्ति जलाने, दुकानों को लूटने, वाहनों में आग लगाने या आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में डालने का अधिकार नहीं बन जाता। यूरोप की हिंसक घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि जब विरोध की सीमा टूटती है, तो सबसे अधिक नुकसान अक्सर उन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हितों की रक्षा का दावा किया जाता है। कारोबार प्रभावित होता है, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, छोटे

काम कर सकती हैं। नागरिकों को किसी भी संदेश या वीडियो को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। यूरोप के हिंसक प्रदर्शनों से भारत को सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। उसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों के भरोसे, संस्थाओं की निष्पक्षता, शांतिपूर्ण असहमति की स्वतंत्रता और कानून के समान अनुपालन में निहित है। आखिरकार किसी भी आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, उसे हिंसा और अराजकता के हवाले करना नहीं।

खबर संक्षेप

आंध्र में 100 शहरी निकाय चुनाव रुका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोगने 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 13 नगर निगमों तथा 87 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव की कार्यवाही रोक दी गई। टीडीपी-बाइएसआरसीपी के बीच जारी हिंसक झड़पों के बीच कोर्ट ने यह कदम उठाया।

कन्नड़ लोगों को नौकरी नहीं तो होगी कार्यवाई

बेलारु। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर निजी संस्थान राज्य में कन्नड़ लोगों को जानबूझकर नौकरी के अवसर नहीं देते हैं, तो सरकार कार्यवाई करेगी। कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अवसरों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अधिकारों, सम्मान और अवसरों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

दशकर्म में झड़प, पीके के सामने चले लाठी-डंडे वैशाली। जिले के राधोपुर विधानसभा क्षेत्र की रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला में शनिवार को 13 वच्चों के दशकर्म कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प हो गई। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में दो पक्षों में मारपीट में सत्तारूढ़ जदयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव गंभीर रूप से घायल हा गए। उनका सर में चोट आई है।

यूपी में वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वाल्मीकि जयंती देशभर में 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगंग
राज्यक्रं- 64102/अ-6/2026-27
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण मंजुलता सोनी बेवा स्व. लखन प्रसाद, जयदेव सोनी आ.स्व. लखन प्रसाद, दोनों निवासी दलीपारा अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है, कि आवेदकगण के पति/पिता स्व. लखन प्रसाद के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला-दरीपारा स्थित नजूल भूखण्ड क्र. 3766, 3767, 3768 रकबा क्रमशः 0.03, 0.03, 0.01 एकड़ भूमि है। भूधारक लखन प्रसाद की मृत्यु दिनांक 18.06.2004 को हो गई है। तदुपरांत उक्त आवेदित भूमि से स्वंग लखन प्रसाद का नाम अतिरिक्त करते हुये आवेदकगण द्वारा स्वयं के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु स्वंग लखन प्रसाद के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त संबंध में जिर्जा किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 05/11/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक- 23/10/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।
नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में आरबीआई के डेटा सेंटर का किया उद्घाटन विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता, वित्तीय सेवाएं अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी होंगी



एजेसी न्यूज नोट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। करीब 169 करोड़ से तैयार इस सुविधा को देश की डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास है और विकास का लाभ गांवों, छोटे शहरों तथा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित, सक्रिय प्रशासन और सुशासन के मॉडल पर काम कर रही है। देश का विकास तभी संतुलित होगा, जब गांवों और छोटे शहरों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यह नया केंद्र डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इससे बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को संचालित करने के लिए सुरक्षित तकनीकी आधार मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भुवनेश्वर के जटनी (इन्फो वैली-2) में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 169 करोड़ रुपए के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास का विस्तार ही हमारी प्राथमिकता है। साथ ही ये भी कहा कि भारत में अब गवर्नेंस की भूमिका बदल रही है।

देश का विकास तभी संतुलित होगा, जब गांवों और छोटे शहरों को भी पर्याप्त अवसर मिलेंगे



आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री

ओडिशा को दी बड़ी सौगात

जटनी स्थित इन्फो वैली-2 में बनाया गया, 18.55 एकड़ क्षेत्र में बना

आरबीआई का यह केंद्र ओडिशा के जटनी स्थित इन्फो वैली-2 में बनाया गया है। यह 18.55 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसकी आधारशिला 22 मार्च 2023 को तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रखी थी। इस परिसर में डेटा सेंटर के साथ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी है। यहां महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियों के साथ अन्य प्रमुख तकनीकी पहलों का संचालन किया जाएगा। डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ बैंकिंग व्यवस्था में डेटा की सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। यह केंद्र वित्तीय आंकड़ों और तकनीकी प्रणालियों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

डिजिटल बैंकिंग ने चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा
प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने देश के लोगों को चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि अब ऐसे लोग भी बैंक से सस्ता और आसान कर्ज ले सकते हैं, जिनके पास गारंटी देने के लिए मजबूत करना है।

वित्तमंत्री सीतारमण ने भी किया संबोधित
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों को दी कर्ज की सुविधा, लोग लाभान्वित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों के लिए बैंक से कर्ज लेना आसान बनाया है। सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए 60 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण खातों में 43 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है।

अब देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले
सीतारमण ने बताया कि 2014 में हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। उनके अनुसार अब देश में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इन खातों में सालाना शुल्क और न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त नहीं है।

वित्तीय सेवाओं की होगी बहोतरी
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में मौजूद डेटा सेंटरों से वैश्विक बलाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए कर छूट की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

डेटा सेंटर डिजिटल युग की तिजोरी के समान: डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ा है। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया है। वित्त मंत्री ने डेटा सेंटर को डिजिटल युग की तिजोरी जैसा बताया। सरकार ने 2022 में डेटा सेंटर को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया था।

कार्यक्रम में ये रहे शामिल

कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम, सीएम मोहन चरण माझी, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव भी थे।



उमड़ा जनसैलाब, 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गुंजा नमो घाट

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रविवार को वाराणसी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस लाइन से नमो घाट तक करीब सात किलोमीटर लंबे मार्ग पर लोगों ने पुष्प वर्षा, दोल-नगाड़ा और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से अपने काफिले के साथ नमो घाट पहुंचे, जहां हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन। उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयर शो में शामिल होना है। इस दौरान लोगों में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्रीका काफिला पुलिस लाइन से सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट, कज्जाकपुरा और राजघाट पुल होते हुए नमो घाट पहुंचा। मार्ग में जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे और बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के दोनों ओर खड़े होकर उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। भद्रजुचुंगी समेत कई स्थानों पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री ने कुछ स्थानों पर वाहन से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन किया। इस दौरान उनके काफिले पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और देशभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया गया।

'नमो-नमो' का उद्घोष किया

नमो घाट पहुंचने पर वायु सेना के अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर 'नमो-नमो' के उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत के लिए जुटे लोगों में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल रहे। घाटी और आसपास के इलाकों में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री खीचवां में अरविंद मिल लिमिटेड की नई टेक्सटाइल इकाई का उद्घाटन कर चुके हैं। 7 एकड़ में स्थापित इकाई में परिधानों का उत्पादन किया जाएगा।

अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन खत्म मंत्री खट्टर ने शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया

नीति आयोग ने विकास पर दिया जोर हम राज्य की राजधानियों से शहरों को नहीं चला सकते

ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर विवाद पर कांग्रेस का सवाल कांग्रेस नेता जानकारी क्यों छिपा रहा चुनाव आयोग? जयशाम ने सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए

एजेसी न्यूज नोट

19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 रविवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री, श्री मनोहर लाल ने समापन सत्र को संबोधित किया और शहरी परिवहन में उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। 23-24 अक्टूबर को सम्मेलन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आयोजित किया गया था। समापन सत्र में ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्रा, ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव उषा पाषो तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी परिवहन विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।

एजेसी नई दिल्ली

नीति आयोग के सदस्य राजीव गोबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शहरी प्रशासन, योजना और वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत में चल रहे जनसंख्यिकीय और शहरी बदलाव के व्यापक दायरे पर जोर देते हुए गोबा ने बताया कि भारत की जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर हो जाएगी। 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है, जिससे शहरी जनसंख्या 85 करोड़ होने का अनुमान है। शहरी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने शहरों की योजना बनाने, प्रशासन और वित्तपोषण के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी।

एजेसी नई दिल्ली

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर विवादित ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि आयोग जानकारी को सार्वजनिक करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि इससे एसआईआर प्रक्रिया में कथित तौर पर हुई बड़े पैमाने की और केंद्रीकृत गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सकती है। विश्वी दल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट में दावा कियाईसीआई ने ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के नाम और उसके संस्करण से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया है।

एआई का किया जा रहा इस्तेमाल

जयराम ने कहा कि आयोग विवादित ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी लगातार छिपा रहा है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर को केंद्रीकृत तरीके से अंजाम देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, भारतीयों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजके खुलासे से यह क्यों पता चला कि ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर उसी ने विकसित किया है?आयोग ने इस जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया? आयोग एसआईआर और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में एआई के इस्तेमाल से बार-बार इनकार क्यों कर रहा है?

डॉक्टर दंपती को 11 लाख रुपए के लिए धमकी

मेरठ, पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर दंपती ने तीन लोगों पर बकाया रकम नहीं लौटाने, झूठे मुकदमे में फंसाने और

जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई। शिकायत के आधार

पर पल्लवपुरम पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंसल कोर्टयाई कॉलोनी निवासी

विजय कुमार शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उनकी पत्नी डॉ. श्रद्धा शर्मा व्यक्ति हैं।

हाईकोर्ट ने मेरठ एसएसपी को 45 मिनट खड़ा रखा शादी से मुकरने वाले को पेश नहीं किया था, एसएसपी बोले- मेरे अफसरों से चूक हुई

मेरठ ,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को मेरठ एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को 45 मिनट तक कोर्ट में खड़ा रखा। मामला शादी का वादा करके जमानत लेने और बाद में मुकरने से जुड़ा है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत रद्द कर ररद को उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन, एसएसपी के जूनियर पुलिस अफसरों ने आरोपी को हाईकोर्ट में नहीं पेश करके सीजेएम की अदालत में पेश कर दिया था। सीजेएम ने आरोपी को जेल भी भेज दिया था। ररद ने हाईकोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि मैं छूट 7टी पर था। मेरे जूनियरों से चूक हुई है।



बीबीजीटीएस मूर्ति, एसएसपी मेरठ

क्षेत्र में पिछले साल एक लड़की के साथ नितीश उर्फ सिद्धांत उर्फ सेठी ने शादी का झांसा देकर रेप किया था। हाईकोर्ट में उसने लड़की से शादी करने का वादा कर जमानत मांगी। 18 मार्च, 2026 को सेठी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलते ही सेठी ने अपना

वादा तोड़ दिया। इस पर लड़की ने हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने आरोपी सेठी की जमानत रद्द करके उसे कोर्ट में हाजिर करने के लिए 28 सितंबर, 2026 को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कई तारीखों के बाद भी पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को मेरठ ररद को व्यक्तिगत पेश होने के आदेश दिए थे। शनिवार को सुनवाई के दौरान लड़की और आरोपी सेठी दोनों कोर्ट में मौजूद थे। जब कोर्ट ने सेठी से पूछा, तो उसने लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ?इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जमानत लेते समय दी गई अंडरटेकिंग का सीधा उल्लंघन किया है। कोर्ट ने तत्काल उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद आरोपी सेठी को जेल भेज दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट से 28 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हाईकोर्ट लाने की जगह सीजेएम, मेरठ की अदालत में पेश कर दिया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस लापरवाही का पता चलते ही हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया इसके बाद शनिवार को हाईकोर्ट में खुद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति पेश हुए। उन्होंने बताया कि वह 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अवकाश पर थे।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छगंग)
राज्यक्रं- /अ-6-अ/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पूर्णिमा टोपे पति गंगाराम टोपेको पिता पंचमराम, निवासी भट्टेरोड, नरसिंहपुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदिका के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 1278/3 रकबा 0.032 हे. स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के पिता का नाम तुटिसिरा सिराजुद्दीन सिद्दीकी अंकित हो गया है जबकि आवेदिका के पिता का वास्तविक नाम पंचम राम है। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपने पिता का नाम सिराजुद्दीन सिद्दीकी के स्थान पर पंचम राम दर्ज कर त्रुटि सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
राज्यक्रं- /20(1)/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका हेमन्त श्यामजी परमार आ०/पति श्यामजी हरि परमार जाति, निवासी डी०सी० रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छगंग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-राम मंदिर मैदान, शीट नम्बर-11 क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4813/78 रकबा 0.03 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26.10.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 26.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
राज्यक्रं/20(1)/2025-26
ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती इंदु देवी आ०/पति लक्ष्मीनारायण अग्रवाल जाति अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छगंग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया निवासी अग्रसेन वाई है कि मोहल्ला-खरसिया रोड, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2823/20, 2824/13 रकबा 0.02 1/4, 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.10.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 15.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 9 नवंबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक जेन्स-2101/3340/2026-जीएडी-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था।

चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ने की संभावना के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े।

शून्य जनहानि का लक्ष्य और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दत्तेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर



जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है। राहत शिविरों को 24 घंटे संचालित रखने और उनमें सभी आवश्यक

सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव को चिकित्सा सुविधाओं की निबांध उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की

सूची तैयार कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के प्रबंध करने को कहा गया है। किसानों को फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने तथा चक्रवात से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुचारु रखने के निर्देश

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बिजली के खंभे गिरने से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए विद्युत विभाग को तैयार रहने को कहा गया है।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम, अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलें - राज्यपाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

आईटीएम विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर रायपुर। राज्यपाल रमन डेका ने युवाओं से अपने नए विचारों को स्टार्टअप में बदलने, नवाचार को अपनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है और युवाओं के विचार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। राज्यपाल आज आईटीएम विश्वविद्यालय, रायपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण



पदक, चार शोधार्थियों को पीएचडी तथा 464 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में

अपार संभावनाएं हैं। युवा अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देकर नए उद्यम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता, ज्ञान और रचनात्मकता के बल पर

रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की एक पारी के समापन और दूसरी पारी की शुरुआत का प्रतीक है। डिग्री केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल के माध्यम से परिवार, समाज और देश के प्रति दायित्व निभाने का अवसर है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही-गलत का विवेक विकसित करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

राज्यपाल ने कहा कि आज के विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मोबाइल के युग में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने डिजिटल लत और नशे की

बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। जरूरत के अनुसार ही मोबाइल का उपयोग करने तथा परिवार, मित्रों और समाज के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने शांति और सुरक्षा से विकास को गति मिलने की बात कही और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद बने विकास के अवसरों तथा बस्तर में आजीविका के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामचंद्र जहांगीर ने स्वागत भाषण दिया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष वी.के. गोयल ने भी संबोधित किया।

दुर्ग। जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो मैक्स पिकअप से 4 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। खुसीपार थाना क्षेत्र के डबरापारा के पास हुई कार्रवाई में वाहन के पिछले हिस्से में बनाए गए विशेष गुप्त चेंबर से नकदी मिली।

रात 11 बजे रोका गया पिकअप

पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन में बड़ी मात्रा में नकदी रायपुर से नागपुर ले जाई जा रही है। इसके आधार पर पुलिस टीम ने डबरापारा के पास रात करीब 11 बजे सफेद रंग के बोलेरो मैक्स पिकअप (क्रमांक



सीजी 04 क्यू 5996) को रोककर जांच की।

पिछले हिस्से में मिला गुप्त चेंबर

जांच के दौरान पुलिस को वाहन का पिछला हिस्सा मॉडिफाई कर पूरी तरह बंद किया हुआ मिला। संदेह के आधार पर सघन तलाशी लेने पर वहां एक विशेष गुप्त चेंबर मिला। इसे खोलने पर अंदर छिपाकर रखी गई भारतीय मुद्रा बरामद हुई।

दो लोगों से पूछताछ जारी पुलिस के अनुसार, वाहन में भवेशभाई जीनाभाई डाभी चालक के रूप में और विष्णुदेव दुबे सवार थे। दोनों से बरामद रकम के वास्तविक स्वामित्व, उसके स्रोत और इसे नागपुर ले जाने के उद्देश्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नकदी के वित्तीय स्रोत और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच के लिए आयकर विभाग को भी सूचना भेजी जा रही है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार: वित्त मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

दुर्ग। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी ने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया है। वित्त मंत्री चौधरी दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित पृथ्वी पैलेस में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ टैक्स टेक समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव तथा जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और



23 प्रकार के उपकर प्रचलित थे। अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के कारण व्यापारियों को अनेक प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन करों को एकीकृत कर देश को एक साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापारियों पर कर अनुपालन का बोझ कम हुआ है और कारोबार सुगम हुआ है। भारतीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगी टैक्स प्रैक्टिस की कार्यप्रणाली

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय तकनीकी परिवर्तन और नवाचार का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। कर प्रशासन, लेखांकन, विधिक अनुसंधान, दस्तावेजों के विश्लेषण और कर अनुपालन जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित तकनीकों का उपयोग नई संभावनाएं

पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य करदाताओं और शासन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें बदलती तकनीकों और आधुनिक डिजिटल उपकरणों की जानकारी होना आवश्यक है।

कानून की शिक्षा में जीएसटी को शामिल करने का सुझाव

कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने विधि शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीएसटी कानून को शामिल करने का सुझाव रखा। प्रतिनिधियों ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान ही जीएसटी कानून की व्यावहारिक जानकारी मिलने से उन्हें भविष्य में बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

शॉर्टकट के चक्कर में खतरे से खेल रहे छात्र, हाफ नदी के जर्जर एनीकट से रोजाना आवाजाही

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कवर्धा। जिले से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिले के अंतिम छोर पर स्थित पंडरिया विकासखंड के ग्राम दामापुर में विद्यार्थी रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। यहां हाफ नदी के शिवांगंगा क्षेत्र में बना एनीकट जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बावजूद स्कूली बच्चे कम दूरी तय करने के लिए इसी टूटे हुए एनीकट को पार कर स्कूल आते-जाते हैं।

शॉर्टकट के चक्कर में खतरे से खेल रहे विद्यार्थी

जानकारी के अनुसार, ग्राम दामापुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी प्रतिदिन हाफ नदी के क्षतिग्रस्त एनीकट को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने का दूसरा सुरक्षित



रास्ता भी उपलब्ध है। नदी पर पुल भी बना हुआ है, लेकिन उस रास्ते से स्कूल पहुंचने के लिए लगभग एक से दो किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इसी दूरी से बचने के लिए विद्यार्थी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, यह रास्ता बेहद जोखिम भरा है। एनीकट का एक हिस्सा टूट चुका है और बाढ़ पानी जमा है।

टूटे एनीकट के नीचे गहरा पानी, हादसे की आशंका

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, एनीकट में फिलहाल पानी का बहाव अधिक नहीं है, लेकिन क्षतिग्रस्त

करना पड़ रहा है। नदी पार करते समय बच्चों के कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। कई बार पानी से उनकी स्कूल ड्रेस भी भीग जाती है। पानी में भीगने और जूते खराब होने के डर से कुछ बच्चे जूता-मोजा पहनकर भी नहीं आ पा रहे हैं।

हर साल अस्थायी मरम्मत, स्थायी समाधान का इंतजार

ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्षतिग्रस्त एनीकट की स्थायी मरम्मत नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि हर साल एनीकट के दोनों छोर पर मिट्टी डालकर अस्थायी मरम्मत कर दी जाती है। लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित नहीं कर पाती। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्कूल पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और पुल उपलब्ध है।

शहीद गुंडाधुर की धरती से लिखी जा रही बस्तर में बदलाव की कहानी

सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा में तब्दील कर दूरदराज के गांवों में पहुंचाई जा रही शासन की विभिन्न योजनाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लघुभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में

विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है।

विकास की मुख्यधारा से जुड़ता बस्तर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के

प्रभावों से मुक्त हो रहा है। ह्यनियद नेल्ला नारह्व योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा: सुशासन और जनविश्वास का प्रतीक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश



के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था नितानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जनवायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के

ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी।

एक ही छत के नीचे मिल रही हैं तमाम सरकारी सुविधाएं

पहले बस्तर के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं, आधार अस्पेटेंट, केवाईसी, मोबाइल लिंक और प्रमाण पत्र

जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं।

महिला स्व-सहायता समूहों से आ रही आर्थिक क्रांति

नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह

पर हैं। स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

आधुनिक बाजार और बेहतर पैकेजिंग से जुड़ रहा बस्तर

इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अब पेशेवर संस्थानों की मदद ली जा रही है।

कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमला सक्रिय, गांवों में गिरदावरी व डिजिटल क्रांप सर्वे का सत्यापन



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में फसल गिरदावरी और डिजिटल क्रांप सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शंकरगढ़ तहसील के ग्राम नावाडीह एवं डीपाडीहखुर्द तथा ग्राम कृष्णनगर (धमनी) में राजस्व अमले ने खेतों में पहुंचकर गिरदावरी की, वहीं विकासखंड वाडुफनगर की रघुनाथनगर तहसील के ग्राम बलंगी और गैना में डिजिटल क्रांप सर्वे का भौतिक सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान खेतों में बोई गई फसलों का मिलान अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों से किया गया। सटीक फसल रिकॉर्ड से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय सहित शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्य समय-सीमा में त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण करने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।

चक्रवाती तूफान से संभावित भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड रहे आपदा प्रबंधन टीम : रेना जमील

0 शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं पर विशेष निगरानी के निर्देश 0 कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। सोमवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने राज्योत्सव की तैयारियों, संभावित भारी बारिश, धान खरीदी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागीय कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से संभावित स्थिति में भारी बारिश को देखते हुए संबंधित अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जलाशयों और बांधों के जलस्तर की नियमित निगरानी रखते हुए संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला एवं अनुभाग स्तर पर कंट्रोल रूम, राहत केंद्रों की व्यवस्था व्यवस्था के साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक दवाइयां एवं राहत-बचाव की तैयारियां रखने को कहा है। ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत एवं आवश्यक सहायता

उपलब्ध कराई जा सके। राज्योत्सव के तैयारियों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला, तहसील एवं जनपद स्तर के सभी शासकीय भवनों में ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने परीक्षा के दृष्टिगत आगामी तीन माह तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक अवकाश नहीं लेने को कहा। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रेगनेंसी के मामलों की नियमित निगरानी करने और सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी बीपीएम को अपने कार्यों में गंभीरता लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर

रोशनी करने को कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण हो और आवेदकों से सकारात्मक फीडबैक भी प्राप्त करें। इस दौरान जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर तथा जनशिकायत के लंबित प्रकरणों को आगामी समय-सीमा की बैठक से पहले निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर विशेष

ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा के दृष्टिगत आगामी तीन माह तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक अवकाश नहीं लेने को कहा। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रेगनेंसी के मामलों की नियमित निगरानी करने और सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी बीपीएम को अपने कार्यों में गंभीरता लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर

ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों को समीक्षा कर किसान पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता एवं सत्यापन की भी जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर श्रीमती नयन तारा सिंह तोमर, राम सिंह ठाकुर, प्रशांत कुशवाहा, एसडीएम सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अनावश्यक शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व में अनुपस्थित शिक्षकों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग की जानकारी ली। टीकाकरण की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध साप्ताहिक उपलब्धि प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग बढ़ाने को कहा। उन्होंने आगामी माह में संभावित प्रसव वाली महिलाओं, विशेषकर हाई रिस्क



सतर्कता जागरूकता सप्ताह, अधिकारियों ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ

जिले में सोमवार से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह की संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर रेना जमील की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।

1 नवंबर तक चलने वाले जागरूकता सप्ताह की थीम सत्यनिष्ठा से समृद्धि रखी गई है। शपथ में सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा से कार्य करने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय रूप से आवाज उठाने और देश के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनो की समस्याएं आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं शासकीय सेवाओं का लाभ सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्रीमती ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। एवं प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुरक्षित बचपन अभियान, छात्रों को दी गई पॉक्सो एक्ट एवं साइबर सुरक्षा की जानकारी

शा.बा.उ.मा.वि. में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण, उनके अधिकारों एवं सुरक्षित वातावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को यहां के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित इस अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराना तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान की थीम जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार तथा मूल संदेश हर बच्चे को बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमांशु पण्डा उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की सरल एवं सहज भाषा में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं अधिकारों का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही विद्यार्थियों को साइबर

अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग, ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतने तथा किसी भी अनुचित परिस्थिति में विश्वसनीय व्यक्ति एवं संबंधित प्राधिकरण से सहायता लेने के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, विधिक सहायता एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में बताया गया। अभियान के तहत प्रथम चरण में 26 से 31 अक्टूबर तक एक सप्ताह का गहन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि द्वितीय चरण में 12 नवंबर से विद्यालय स्तर पर क्षमता निर्माण एवं जागरूकता गतिविधियां निरंतर संचालित की जाएंगी।

यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष थॉमस एफ्रा के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण की सचिव सुश्री पायल टोपनो के निदेशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुश्री प्रमोद कुंज, प्रभारी शिक्षक ओमप्रकाश गजबाड़े तथा फैलीगल वॉलंटियर्स सत्य नाथयण एवं उमेश गजबाड़े उपस्थित रहे।

कल प्रेमनगर आएंगे मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के प्रेमनगर में बुधवार 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने सोमवार को नगर पंचायत प्रेमनगर पुष्प वाटिका के समीप कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन, हेलीपैड स्थल, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया

जायेगा। जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागीय स्टॉल लगाई जाएंगी। पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया जाएगा। तीरंदाजी प्रतियोगिता, युवा संवाद आयोजन सहित दिव्यांजनों हेतु शिविर भी लगाई जाएंगी। कलेक्टर श्रीमती जमील ने उपस्थित सभी अधिकारियों को

सभी तैयारियां निर्धारित तिथि से पूर्व समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, प्रशांत कुशवाहा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी तैयारियां निर्धारित तिथि से पूर्व समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, प्रशांत कुशवाहा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध, भाजयुमो ने फूँका खरगे का पुतला, किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई अशुभ एवं अमर्यादित बयानबाजी के विरोध में सोमवार को भाजयुमो ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी के मार्गदर्शन एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खरगे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प और झुमाझुटकी हुई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के कड़े प्रयास किए गए, लेकिन आक्रोशित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हुए इस कड़े संघर्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला फूँका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि यह विरोध प्रदर्शन भारतीय

जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के निर्देशन एवं भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के आह्वान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर



सुनिश्चित किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पटेल ठाकुर, राजू साहू, लोकप्रिय जननेता के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की ओखी मानसिकता और हताशा को दर्शाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक

कार्यकर्ता और देश का युवा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रितेश गुप्ता, जिला

उपाध्यक्ष संत सिंह, जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी, दीपक गुप्ता, बबलू गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, वार्ड पार्षद बिसेन तायल, सोनू गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मंडल महामंत्री नीरज जिन्दिया, भाजयुमो जिला मंत्री सहीम अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी दीक्षित वर्मा, कार्यालय मंत्री सोनू साहू, विशाल गुप्ता, विकी सोनवानी, मंडल अध्यक्ष दिलीप साहू, महामंत्री हर्ष गुप्ता, महेंद्र साहू, गौरी शंकर साहू, अमन साहू, प्रिंस साहू, शानू साहू, गौरव दुबे, उगेंद्र राजवाड़े, हेमंत बैगा, पटेल ठाकुर, राजू साहू, कृष्णा राजवाड़े, भुनेश्वर साहू, बलू साहू, मनोज साहू, महेंद्र साहू, रविंद्र साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यकर्ता और देश का युवा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रितेश गुप्ता, जिला

उपाध्यक्ष संत सिंह, जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी, दीपक गुप्ता, बबलू गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, वार्ड पार्षद बिसेन तायल, सोनू गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मंडल महामंत्री नीरज जिन्दिया, भाजयुमो जिला मंत्री सहीम अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी दीक्षित वर्मा, कार्यालय मंत्री सोनू साहू, विशाल गुप्ता, विकी सोनवानी, मंडल अध्यक्ष दिलीप साहू, महामंत्री हर्ष गुप्ता, महेंद्र साहू, गौरी शंकर साहू, अमन साहू, प्रिंस साहू, शानू साहू, गौरव दुबे, उगेंद्र राजवाड़े, हेमंत बैगा, पटेल ठाकुर, राजू साहू, कृष्णा राजवाड़े, भुनेश्वर साहू, बलू साहू, मनोज साहू, महेंद्र साहू, रविंद्र साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिले में जल जीवन मिशन योजना पर लगा ग्रहण, भुगतान के अभाव में नहीं हो रहे काम

आज रायपुर में अर्धनग्न हो कर भीख मांगेंगे जल जीवन के ठेकेदार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में हर घर जल योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुए थे लेकिन विभाग के द्वारा पहले पानी की व्यवस्था करनी थी उसके बाद हर घर नल कनेक्शन हेतु निविदा आमंत्रित करनी थी परंतु विभाग द्वारा पहले हर घर नल योजना के कार्य पूर्ण करा लिए अब पानी की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ करने की तैयारी की गई है। पी एच ई ठेकेदार संघ के द्वारा विभाग को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जिला की समस्त समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है पर वह पूर्ण नहीं हुआ है।

11 एमवीएस योजना में से 6 योजना की निविदा निष्पादित नहीं हुई है। यह भी विचारणीय है कि 11 एमवीएस योजना अंतर्गत 543 में से 413 ग्राम की एमवीएस योजनाएं जल आपूर्ति हेतु आश्रित है। आश्रित योजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जबकि इन्हें न तो जलापूर्ति मिल पा रही है न ही इनका रनिंग

बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन संचालक द्वारा 19 फरवरी 2026 को आदेश क्र. 547 में रनिंग बिल भुगतान अनुबंधित राशि का मात्र 70 प्रतिशत राशि तक भुगतान हेतु



आदेश किया गया जिसके बाद 11 अगस्त को आदेश क्र. 2397 में 60 प्रतिशत राशि तक कर दिया गया। किन्तु विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जो प्रशासन की नीयत पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह सभी प्रशासनिक गतिविधियां शासन की महत्वाकांक्षी योजना की खिल्ली उड़ा रही है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा मौखिक आदेशों के तहत ठेकेदार को जल स्रोत उपलब्ध कराने विवश किया जा रहा है जबकि यह दायित्व

स्पष्ट रूप से विभाग का है एवं इस हेतु एमवीएस योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की गयी थी। आधी से अधिक एमवीएस योजनाओं का अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ है एवं कार्ययत

योजनाओं का भुगतान पिछले 1 वर्ष से नहीं होने के कारण इकाइयां कार्य बंद कर चुकी हैं। परिणाम स्वरूप आश्रित एमवीएस योजनाएं भुगतान की बाट जोह रहीं हैं। अब यदि जलस्रोत भी उपलब्ध है तो ठेकेदारों के पास कार्यशील पूंजी नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण करना असंभव है। केंद्र द्वारा वर्ष 2028 तक हर घर जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु विभाग की नीतियों और जल जीवन मिशन के प्रति उदासीनता इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अवरोध बनी हुई है। प्रदेश स्तर पर अन्य जिलों की समस्याओं के साथ अपनी समस्या हेतु अर्धनग्न हो कर भीख मांगने के लिए आज 27 अक्टूबर को रायपुर में समस्त जल जीवन के ठेकेदार समूह ने एकत्रित होने का आह्वान किया है।

जनहित के मुद्दों पर प्रेमनगर ब्लॉक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सड़क, स्वास्थ्य व बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। प्रेमनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को जनहित की प्रमुख समस्याओं को लेकर ब्लॉक स्तरीय धरना-प्रदर्शन एवं चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामानुजनगर से तारा मार्ग की जर्जर एवं अधूरी सड़क, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों

कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक गुलाब कमरो, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष



शशि सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के जागरूक लोग उपस्थित रहे।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद यादव, मेंहदी यादव, स्माइल खान, रोहित कनौजे,



दीपन मानिकपुरी तुलसी यादव, सुखमनिया जगते, , आलोक साहू, बसराम सोरी, असकरण गुप्ता, अखिलेश जायसवाल

कमलेश्वर सिंह विजय देवांगन, रमेश साहू रोशन पावले धर्मेन्द्र प्रजापति, विजय महंत, दिनेश



सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है।

कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, सिंहदेव बोले-वोट चोरी से लोकतंत्र खतरे में

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर। कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तीसरे चरण के तहत अंबिकापुर में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकारवार्ता में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। सिंहदेव ने आरोप लगाया कि देशभर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का खेल चल रहा है, आयोग नियमों के विपरीत काम कर रहा है। इस दौरान एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष पटनायक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग भी मौजूद रहीं। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक मुद्दा है जिसमें दोहरा पंजीकरण, ईवीएम-वीवीपीएटी, चुनाव संबंधी आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी शामिल है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख मतदाता बढ़े, जिसमें से 32 लाख सिर्फ 5 महीने में जोड़े गए। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में 1,00,250 वोट प्रभावित होने का आरोप लगाया गया, जिसमें



स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने पर सिंहदेव ने कसा तंज

पत्रकारों के सवाल पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि, स्मृति ईरानी अगला चुनाव यहां से लड़ने वाली हैं। भाजपा में जीतने लायक स्थिति नहीं लग रही, तभी उन्हें इतना हाईलाइट किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह अंदरूनी मामला है। मैं तो स्मृति ईरानी से बस शककर के भाव की बात करना चाहता हूं, वो बता दें कि उन्होंने कितना शककर का भाव कहा था यूपी में जब वो चुनाव लड़ी थीं और आज देश में उनकी पार्टी ने कहा पहुंचा रखा है, फिर आगे की बात। सिंहदेव ने कहा कि भाजपा महंगाई के मुद्दे पर बात करने से बच रही है।

फॉर्म-6 का दुरुपयोग और एक ही पते पर कई वोटर शामिल हैं। पीलीभीत का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां बिना फॉर्म भरे 13 हजार मतदाताओं के नाम बदल दिए गए। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर 2026 की पड़ताल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन 30 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई वह प्राारूप मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। देशभर में लगभग 27 लाख नाम अंतिम रूप से हटाए गए और 38 लाख अपीलें लंबित हैं।

मूल आंकड़े डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएं

एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष पटनायक ने कहा कि, वोट चोरी एक व्यापक मुद्दा है। कांग्रेस की मांग है कि मूल आंकड़े डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएं ताकि स्वतंत्र सत्यापन हो सके। कांग्रेस संबंधित रिकॉर्ड और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। आरोप है कि, आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। 2023 के कानून ने सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने कांग्रेस के आगामी अभियान के बारे में विस्तार से बताया।

रैली की तैयारियों को लेकर बीएलओ की बैठक

कांग्रेस के वोट बचाओ-देश बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण और 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमिटी सरगुजा और बीएलओ की महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक देवाशीष पटनायक ने की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया गैर संवैधानिक थी। इसके जरिए देश के 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस देश विरोधी कार्य के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, देश के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैतफलांग ने तीसरे चरण के आंदोलन की जानकारी साझा करते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुटने का आह्वान किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह ने भी चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि देश में माहौल बता रहा है कि भाजपा साफ होने वाली है, लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे चुनाव में उतरेगी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निष्फल करना है।

एआईसीसी ऑब्जर्वर देवाशीष ने बृथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठनात्मक समीक्षा की। कांग्रेस अब सरगुजा संभाग में बृथ स्तर पर 'वोट रक्षक' तैनात कर मतदाता सूची का सत्यापन करेगी और 25 नवंबर तक गांवों में चौपाल और दिल्ली चलो कार्यक्रम चलाएगी।

गुप्ता, पूर्व विधायक, रामदेव राम, इरफान सिद्दीकी सहित अन्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, मो. इस्लाम, कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

1.25 लाख से अधिक पीवीटीजी लाभार्थियों तक पहुंचीं एमएमयू



छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर।

सुदूर जनजातीय समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हुए, छत्तीसगढ़ में पीएम-जनम मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम ने 18 जिलों में संचालित 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से 1,25,051 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लाभार्थियों तक अपनी पहुंच बनाई है। 31 दिसंबर 2025 को अपनी शुरुआत के बाद से, इस कार्यक्रम के तहत 15,209 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं। 2,45,095 रोगियों के पंजीकरण और 3,32,526 परामर्श दर्ज किए गए हैं, तथा 2,94,560 नैदानिक जांचें (डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन) की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत

1,28,596 फॉलो-अप रोगी रिकॉर्ड और अस्पताल रिफरल के 3,671 मामले भी दर्ज किए गए हैं। ये मोबाइल इकाइयां गांवों और सुदूर टोलों तक सीधे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, जिससे चिकित्सा परामर्श, प्रयोगशाला जांच, स्क्रीनिंग, दवाइयां और रिफरल सहायता

हैं, जिससे बीमारियों की समय पर पहचान और त्वरित चिकित्सीय उपचार में मदद मिल रही है। धनुष हेल्थकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालन सहयोग से लागू की गई यह पहल, कमजोर जनजातीय आबादी तक पहुंचने और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने में मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को दर्शाती है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि, सुदूर व वंचित पीवीटीजी समुदायों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल, जांच सेवाएं और फॉलो-अप देखभाल मिलती रहे।

मन की बात श्रवण करके घुनघुट्टा नदी तट पर छठ महापर्व की तैयारियों पर चर्चा

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर। श्री राम छठ घाट उदयपुर ढाब में रविवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 139 वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, भाजपा अंबिकापुर ग्रामीण के अध्यक्ष विवेक सिंह सेंगर एवं एल्डरमैन श्रीधर केसरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छठ घाट समिति के अध्यक्ष आचार्य दिनेश मिश्र, समिति के कोषाध्यक्ष दिगम्बर सहित पूरी समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राम छठ घाट घुनघुट्टा नदी के तट पर स्थित है। यह उत्तर वाहिनी नदी है। यहां प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई है। घाट पर पक्का निर्माण कार्य भी किया गया है। समिति ने सभी छठ व्रती माता-बहनों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस वर्ष भी श्री राम छठ घाट में आकर शुद्ध



और सुरम्य वातावरण में उत्तर वाहिनी घुनघुट्टा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना और छठी मैया की पूजा में शामिल हों। इसी क्रम में मन की बात श्रवण के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के माध्यम से देश के सामान्य नागरिकों की असाधारण उपलब्धियों को सामने लाते हैं और सांस्कृतिक विरासत, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार सगे भाई घायल हुए, एक की मौत, दूसरा गंभीर

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर। जशपुर जिले के थाना बगीचा अंतर्गत सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय पुलिस ने मामले में मार्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, नवरंग राम प्रजापति पिता दिनेश राम प्रजापति 22 वर्ष, जशपुर जिला के बगीचा थाना अंतर्गत ग्राम पसिया कुम्हारपारा के रहने वाला था। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि सुबह उनके दोनों लड़के नवरंग और नन्देश्वर अपने दोस्त सहदेव पैकरा के साथ थाना होने के लिए ग्राम बिमड़ा गए थे। शाम करीब 6 बजे उनके तीनों मोटरसाइकिल में घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान थाना बगीचा क्षेत्र के घोघरामड्डा, पतरापा राड में शाम करीब 6.40 बजे सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर गए। हादसे में सहदेव पैकरा को साधारण चोट आई थी, वहीं पीछे बैठे दोनों भाई नवरंग और नन्देश्वर को गंभीर चोटें आई थी। घटना की सूचना सहदेव ने नवरंग के स्वजन को दी, इसके बाद वे मौके पर पहुंचे। इन्हें संजीवनी 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर स्वजन पहुंचे, यहां इलाज के दौरान नवरंग की रात 11.45 बजे मौत हो गई। घायल नन्देश्वर को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हायर सेंटर रायपुर रेफर कर दिया है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

देश के सबसे तेज धावक अनिमेष कुजूर का सरगुजा पुलिस ने किया सम्मान

आईजी अंकित झा ने बताया युवाओं के लिए प्रेरणा

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर।

सरगुजा पुलिस परिवार के लिए रविवार का दिन गौरव का दिन रहा। देश के सबसे तेज धावक अनिमेष कुजूर को रक्षित केंद्र अंबिकापुर में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। अनिमेष सरगुजा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अमृत कुजूर के सुपुत्र हैं।

यह सम्मान समारोह पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित झा और डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में आयोजित किया गया। समारोह में आईजी सरगुजा रेंज और डीआईजी एवं एसएसपी ने अनिमेष की उपलब्धियों को असाधारण बताते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे सरगुजा ही नहीं, देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। अनिमेष कुजूर ने एथलेटिक्स में इतिहास रचा है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में 10.14 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर जर्मनी के वेट्ज़लर में विश्वी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। साथ ही 200 मीटर में 20.32 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वे



'साइबर जागृति अभियान' में 'सरगुजा पुलिस' रेंज में प्रथम

समारोह के अंत में सरगुजा पुलिस को एक और बड़ी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए 'साइबर जागृति अभियान' में सरगुजा पुलिस ने सरगुजा रेंज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस पर आईजी सरगुजा रेंज द्वारा डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक बंसोड़, प्रशिक्षु आईपीएस डीएसपी तुल सिंह पट्टावी, रक्षित निरीक्षक तुषि सिंह राजपूत, प्रशिक्षु सूबेदार पेमिन वर्मा, प्रशिक्षु सूबेदार गुलशन चंद्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

डायमंड लीग में दौड़ने वाले और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक हैं। 2 जून 2003 को जशपुर जिले के ग्राम घुंटागांव में जन्मे अनिमेष एक पुलिस परिवार से आते हैं। 2026 में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है।

उनका सफर कड़ी मेहनत और अनुशासन की मिसाल है। उन्होंने एशियाई खेल 2026 और एशियाई रिले चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जबकि सीनियर फेडरेशन कप 2026 एक पुलिस परिवार से आते हैं। 2026 में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है।

गर्भाशय कैंसर की सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर।

उत्तर सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में संकल्प हॉस्पिटल ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब गर्भाशय कैंसर से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए बिलासपुर और रायपुर जाने की परेशानी कम हो सकती है। हॉस्पिटल में ख्यातिर्लाभ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. अंकिता गोयल के नेतृत्व में गर्भाशय कैंसर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से बहुत छोटे चीरे से और ऑपरेशन के बाद आवश्यकतानुसार कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कीमोथेरेपी हेतु डॉ हिमांशु गुप्ता की सेवाएं उपलब्ध रहती है। डॉ. अंकिता गोयल ने बताया कि पिछले महीने गर्भाशय कैंसर से पीड़ित लगभग छह मरीजों का ऑपरेशन किया गया। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। मरीजों को आगे की आवश्यक देखभाल और चिकित्सकीय परामर्श भी संकल्प हॉस्पिटल में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को लंबी दूरी की यात्रा, अतिरिक्त खर्च और समय की परेशानी से राहत मिल रही है। डॉ. गोयल ने महिलाओं से अपने



स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए बताया कि मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव, पीरियड्स के बीच असामान्य रक्तस्राव, अत्यधिक या लंबे समय तक माहवारी, असामान्य योनि स्राव तथा पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर समय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है। गर्भाशय कैंसर का उपचार बीमारी की अवस्था और मरीज की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसमें आवश्यकतानुसार सर्जरी और कीमोथेरेपी शामिल हो सकती है। संकल्प हॉस्पिटल में इन सेवाओं की उपलब्धता से सरगुजा एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अपने शहर में ही उपचार और आगे की देखभाल प्राप्त करने का बेहतर विकल्प मिल रहा है। समय पर जांच, सही उपचार और नियमित चिकित्सकीय परामर्श गर्भाशय कैंसर से मुक्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सीतापुर को मिलेगी 4 किमी फोरलेन की सौगात, मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल भूमिपूजन

छ.ग.फ़्रंटलाइन सीतापुर। वर्षों से जर्जर सड़क, गहरे गड्ढों और उड़ती धूल की मार झेल रहे सीतापुर नागरवासियों के लिए राहत की खबर है। नगर की मुख्य सड़क को फोरलेन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका भूमिपूजन 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अंबिकापुर प्रवास के दौरान यह भूमिपूजन कार्यक्रम सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के विशेष आतिथ्य एवं अधिकारियों तथा नागरवासियों की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीतापुर नगर की यह मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। जगह-जगह बने गड्ढे, उड़ती धूल और बदहाल आवागमन स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। दुकानदार, व्यापारी, स्कूली बच्चे और राहगीर सभी को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूल के बीच जीवनयापन करना लोगों की मजबूरी बन गया था। फोरलेन निर्माण की खबर से नागरवासियों में हर्ष है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बनने से नगर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।

विधायक ने कहा-सुगम आवागमन की मिलेगी सुविधा



विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि नागरवासियों ने वर्षों तक जर्जर सड़क और धूल की समस्या झेली है। लोगों की इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने लगातार बेहतर सड़क के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की परिकल्पना के अनुरूप सीतापुर विधानसभा में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। यह फोरलेन सड़क नगर के विकास और सुगम आवागमन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। भूमिपूजन के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने पर सीतापुर को जाम, धूल और गड्ढों से निजात मिलेगी।

ऑटो चालक से हथियार दिखाकर लूट, फरार आरोपी बुलेट वाहन के साथ गिरफ्तार

छ.ग.फ़्रंटलाइन अंबिकापुर। थाना गांधीनगर पुलिस ने ऑटो चालक से डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जप्त की गई है। इस मामले में पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तार कर चला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक, मामला 12 मई 2026 की रात का है। धर्मेन्द्र यादव पिता गणेश प्रसाद यादव निवासी कल्याणपुर, थाना जयनगर, शादी समारोह से ऑटो लेकर कोलडीहा से अपने घर जा रहा था। रात करीब 12.40 बजे ग्राम चंभरी गेरवाली नाला के पास 6 पल्सर पर सवार 10-12 लड़कों ने पीछा कर ऑटो के सामने बाइक लगाकर उसे रोक लिया। आरोपियों ने जेब से गन निकालकर जान से मारने की धमकी दी और एकवा कंपनी का मोबाइल लूटकर भाग गए। प्राथी की रिपोर्ट पर बीते 13 मई को थाना गांधीनगर में धारा 126(2), 310(2)बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।